A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 29 मार्च, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 22, अंक 198, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

विकास के बजाए विवादित मुद्दे बने हैं सत्ता का आसान रास्ता

योगेंद्र योगी

गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंदिर-मस्जिद विवाद पर नेताओं ने जम कर रोटियां सेंकी। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हिंसा में पांच लोग मारे गए। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह के विवाद पैदा हो गए।

बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, लिंगभेद, चिकित्सा और आधारभूत जैसी सुविधाओं के समाधान के बजाए देश के नेता इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर वोट पाने का आसान रास्ता चुन रहे हैं। इसी क्रम में नया विवाद महाराणा सांगा पर दिए गए बयान पर पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी के लोगों का ये तकियाकलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। सपा सांसद रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिन्दुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते?

सांसद सुमन की राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग आज नहीं बल्कि 1000 वर्षों के भारत के इतिहास की समीक्षा करते हैं, वे बाबर और राणा सांगा की तुलना कभी नहीं कर सकते और उन्हें एक ही तराजू पर नहीं रख सकते। महाराणा सांगा ने आजादी की अलख जगाई थी। उन्होंने भारत को गुलामी से बचाया और साथ ही भारत की संस्कृति को सनातनी बनाए रखने में भी अहम योगदान दिया। कुछ क्षुद्र और छोटे दिल वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब नेताओं ने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह के विवादों को हवा दी है। इससे पहले भी ऐतिहासिक मुद्दों पर देश में दरार डालने के प्रयास होते रहे हैं।

बॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसमें राजपूत समुदाय ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। इस विवाद का परिणाम यह निकला कि चित्तौडगढ़ के किले में स्थित 'पद्मावती' महल में अराजक तत्वों ने उन शीशों को तोड़ दिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं आईनों के जरिए राजपूत रानी पद्मावती को देखा था। इसी तरह तीन साल पहले बॉलीवुड फिल्म पानीपत से शुरू हुआ विवाद एक टीवी धारावाहिक तक आ पहुंचा। धारावाहिक में खांडेराव होल्कर से पूर्व महाराजा सूरजमल को युद्ध में हारना दिखाया गया। वहीं, इतिहासकारों का दावा है कि पूर्व महाराजा सूरजमल कभी युद्ध नहीं हारे। बल्कि खांडेराव होल्कर की मौत उनके साथ युद्ध में हुई थी। इसको लेकर रूपवास व कुम्हेर थाने में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गईं। मैसूर के राजा रहे टीपू सुल्तान की 10 नवंबर को मनाई जाने वाली जयंती को लेकर भी खूब कलह हुआ है। मैसूर का शेर कहलाने वाले टीपू की जयंती की शुरुआत कांग्रेस के शासन में हुई लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती रही।

कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर नौबत यहां तक आ गई कि कई शहरों में सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लगाई गई और विरोध प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिन्दू संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि वह टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का कार्यक्रम और उन्हें महिमामंडित करने की योजना रोक दें। बीजेपी की निगाह में टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से कट्टर और हिन्दू विरोधी शासक था। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने उत्तर भारत के 9वीं सदी के राजपूत शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें एक गुज्जर बताया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने जौनपुर गांव में सम्राट मिहिर भोज की एक प्रतिमा भी समर्पित की, जिसमें उन्हें गुज्जर बताया गया। इसका राजपूत समुदाय ने कड़ा विरोध किया। बिहार में गठबंधन से पहले भाजपा ने नीतीश सरकार पर इतिहास के छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने यहां तक कहा था कि सरकार ने प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का अपमान किया है। बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने बिहार सरकार खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोहम्मद युनूस को बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बताते हुए उनके जन्म दिवस पर राजकीय जयंती समरोह मनाए जाने को बिहार केसरी श्रीकृष्ण सिंह का अपमान बताया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंदिर-मस्जिद विवाद पर नेताओं ने जम कर रोटियां सेकी। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हिंसा में पांच लोग मारे गए। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह के विवाद पैदा हो गए। अजमेर में दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा करते स्थानीय अदालत में मामला दायर किया गया। इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी मस्जिदों में मंदिर होने को लेकर अदालतों में मामले दायर किए गए। नेताओं ने तभी पैर पीछे खींचे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवादों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूजा स्थल अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक देश में मंदिर-मस्जिद विवादों से जुड़े नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते, और न ही कोई चल रहा मामला सर्वेक्षण या अंतिम आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है।

यह विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद पैदा हो गया। इस पर भाजपा और विपक्षी दलों ने आरोप-प्रत्यारोप लगा कर देश का माहौल गर्माने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि नागपुर में हिंसा भड़क उठी। इसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। आम लोगों को कर्फ्यू के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे विवादों की चपेट में अक्सर देश का मजदूर, गरीब और कामकाजी वर्ग आता है। इन विवादों की जड़ में आसान सत्ता की राजनीति की चाहत है। दरअसल नेताओं को पता है कि देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, जबकि ऐसे विवादों के जरिए लोगों को बरगला लाकर सत्ता आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार जाएंगे

पटना में 'संविधान सुरक्षा सम्मेलन' में होंगे शामिल

बिहार चुनाव से पहले तीन महीने में यह तीसरा दौरा

पटना (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। पटना के एसकेएम हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित 'संविधान सुरक्षा सम्मेलन' में शामिल होंगे। राहुल गांधी का इस साल ये तीसरा दौरा है। इससे पहले 18 जनवरी और 5 फरवरी को पटना पहुंचे थे। कांग्रेस ने संविधान सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करने वाले सभी संगठनों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे संकट के समय जब संविधान पर खतरे के गिद्ध मंडरा रहे हों, न्याय योद्धा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे संविधान सुरक्षा आंदोलन में भागीदार बनें। चुनावी साल में राहुल के दौरे का काफी अहम माना जा रहा है। 18 जनवरी और 5 फरवरी के बिहार दौरे के बाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था। अब जिलाध्यक्षों की नई टीम तैयार करने के लिए स्क्रूटनी कमिटी बनाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को भी ऐक्टिव कर दिया गया। 2 दिन पहले बिहार के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक में भी राहुल गांधी के तेवर दिखे थे।

कर्मयोगी भाव, भावनाओं के साथ प्रतिबद्ध प्रयास समय की जरूरत : राज्यपाल

प्रदेश राष्ट्र नीति के संकल्प पथ पर प्रतिबद्धता के साथ बढ़ रहा : सीएम

● सीएम बोले-एमपी में तमिल-तेलुगू जैसी भाषाओं में पढ़ाएंगे, जो छात्र इनमें जाएंगे

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश इतिहास के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां से साफ दिख रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। कर्मयोगी भाव, भावनाओं के साथ विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध प्रयास समय की जरूरत है। कर्मयोग दैनिक जीवन में उच्चतर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का वह रास्ता है जो व्यक्तिगत उन्नति के साथ समाज सुधार और सेवा का प्रभावी साधन है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश राष्ट्र नीति के संकल्प पथ पर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी विभिन्न भाषाए, बोलियां, मनोभाव और मूकभाव सभी संस्कृति के वह आभूषण है, जिन पर हमें गर्व है। प्रदेश में अन्य भाषाओं तमिल, तेलुगू आदि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए कमेटी बनाई जाएगी। यह बातें राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में कही। कार्यशाला का आयोजन राजभवन मध्यप्रदेश द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के सहयोग से किया गया था।

कार्यशाला कर्मवाद के पुर्नजागरण की पहल : डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कर्मयोगी कार्य शाला का आयोजन अद्भुत है। कार्यक्रम का भाव और भावना अभूतपूर्व है। सौभाग्य की बात है कि 5 हजार वर्ष पूर्व प्रदेश की धरती से शिक्षित कर्मयोगी के कर्मवाद का पुनर्जागरण प्रदेश से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर्मयोगी ऋषि परंपरा का अक्षरक्ष : प्रतिरूप है। प्रधानमंत्री जी के मनोभावों के आधार पर सुशासन के दृष्टिगत होने वाले सभी सुशासन के प्रयोगों को अंतिम कड़ी तक पहुँचाने का प्रयास मिशन कर्मयोगी है। निष्काम भाव, अहंकार से मुक्त बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए निरंतर कार्य करना ही कर्मयोग है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की विशालता अद्भुत है, जो अतिरंजित बातों को भी सुन लेती है। सही, अच्छी बातों को सद्भावना के साथ लेकर आगे चलती है। इसी लिए आज दुनिया भारतीय दर्शन से प्रेरणा प्राप्त कर रही है।

सुप्रभात

मैंने हर बार सोचा
अपनी साँसों का
हिसाब दे दूं

मैंने हर बार सोचा
सबका दर्द
दूर कर दूं

मैंने हर बार सोचा
नफरत को
जमीन में गाड़ दूं

मैंने हर बार सोचा
हर घर की दीवार पर
प्रेम के अक्षर लिख दूं

मैंने हर बार सोचा
एक नयी हरीभरी
दुनिया बना दूं

लेकिन ऐसा हो न सका
बेचैन
बना रहता हूँ।

\- दुर्गाप्रसाद झाला

म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही

● 144 लोगों की मौत, हजारों घायल,विशाल इमारतें,पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए

बैंकाक (एजेंसी)। म्यांमार और थाईलैंड में रिक्टर पैमान पर 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। इस तेज भूकंप की वजह से दोनों ही देशों में भारी तबाही मची है। 144 लोगों की की मौत हो गई और 732 घायल बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग लापता, 3 की जान गई विशाल इमारतें और पुल ढह गए हैं। थाईलैंड के पीएम शिनवात्रा ने शुक्रवार को बैंकाक के अंदर आपातकाल का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। इसका भारी असर थाईलैंड तक हुआ है। बताया जा रहा है कि बैंकाक में विशाल इमारत के ढहने से उसमें 43 लोग फंस गए हैं। आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि बैंकाक के चाटूचाक पार्क की इस इमारत के अंदर 50 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि म्यांमार में भी भारी तबाही हुई है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रसारित थाईलैंड के बैंकाक शहर के एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत धूल के गुबार के बीच ढहती नजर आ रही है और वहां मौजूद लोग चीखते-चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। पुलिस ने 'एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि वे बैंकॉक के 'चटुचक मार्केट' के पास स्थित घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। वहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है।म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण-पश्चिम चीन समेत 5 देशों में असर देखा गया। यहां के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए।

महाभारत के प्रसंगों की सुंदर प्रस्तुति कर्णभार

विक्रमोत्सव

डॉ. जफर महमूद
उज्जैन से

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमोत्सव के अंतर्गत विक्रम नाट्य समारोह के सप्तम संध्या कावलम्

नारायण पणिक्कर (त्रिवेंद्रम) निर्देशित नाटक कर्णभार का मंचन हुआ। कर्णभार या कर्ण की पीड़ा शाब्दिक रूप से कर्ण का बोझ। भारतीय नाटककार भास द्वारा लिखित एक संस्कृत एकांकी नाटक है । भास भारतीय नाटककारों में अग्रिम हैं। उनकी प्रशंसा कालिदास ने भी अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम के शुरुआत में की है। नाटक कुरुक्षेत्र युद्ध के पिछले दिन कर्ण की मानसिक पीड़ा का वर्णन करता है। कर्णभार मूलतः भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रकरण का पुनर्कथन है। नाटक में कहानी को एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। यह शायद क्लासिक संस्कृत साहित्य में एकमात्र संभावित त्रासदी है।

नाटक की कहानी भारतीय महाकाव्य 'महाभारत' पर आधारित है। कुंती ने कर्ण को तब जन्म दिया जब वह कुंवारी थी। उनके पिता सूर्य देव हैं। कुंती ने कर्ण को उसके जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया और सारथी अतिराधा और उनकी पत्नी राधा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। कर्ण राजाशाही के जीवन से दूर सामान्यप रूप से पले बड़े। कुंती के पाँच बेटे, पांडव और उनके चचेरे भाई, कौरव बचपन से ही दुश्मन बन गए। जब पांडवों और उनके शिक्षक ने कर्ण का अपमान किया, तो उन्होंने कहा कि वह एक निम्न व्यक्ति है जिसे धनुर्विद्या में राजा के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा करने का कोई अधिकार नहीं है, कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण और कौरवों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गये। कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी अंततः राज्य पर शासन करने के अधिकार के लिए एक पूर्ण युद्ध में विकसित हुई। इस युद्ध में, कर्ण कौरव सेना के सेनापतियों में से एक बन गया। जैसे ही कर्ण युद्ध की कमान संभालने वाला था, उसकी माँ कुंती ने उसे उसका असली वंश बताया और उससे विनती कर कहा कि वह युद्ध में अपने ही भाई अर्जुन को न मारे। इससे कर्ण एक शर्मनाक स्थिति में आ गया, क्योंकि वह न तो उसकी विनती को स्वीकार कर सका और न ही अस्वीकार कर सका। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म चमकदार बालियों और छाती पर सुरक्षा कवच के साथ हुआ था। जब तक उसके पास ये थे, कोई भी उसे नहीं मार सकता था। यह जानकर, अर्जुन के पिता इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं । उपहार के रूप में कर्ण के कवच और बालियाँ मांगते हैं। अपने परोपकार के लिए प्रसिद्ध कर्ण ने स्वेच्छा से उन्हें दे दिया। और यह उसके पतन का कारण बनता है।

मंझे हुए कलाकारों ने सशक्त अभिनय से ऐतिहासिक नाटक को प्रभाव पूर्णता से मंचित किया। देश के ख्यातनाम रंग निदेशक पाणिकर को नाटक के क्षेत्र में पद्मभूषण से नवाजा गया था।उन्होंने यह नाटक 1984 में तैयार किया था। 2016 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कला मंडली सोपानम नाट्य प्रदर्शन में संलग्न है।

मुख्यमंत्री जी मेरी पत्नी को सजा दिलाओ

शख्स बोला- उसके 4 बॉयफ्रेंड, मेरठ ड्रम कांड की तरह करवा सकती है हत्या

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में एक शख्स अपनी ही पत्नी से जान का खतरा बताते हुए बीच चौराहे पर धरने पर बैठ गया है। उसने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। युवक एक कागज भी दिखा रहा है। उस पर लिखा है -मुख्यमंत्री जी मेरी पत्नी को सजा दिलाओ। उसने मुझे धोखा दिया है। मेरे बेटे की हत्या की है। मेरी भी हत्या करवा सकती है। देश में पत्नी द्वारा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने के हाल ही में कई मामले सामने आ चुके है। मेरी पत्नी के भी 3-4 बॉयफ्रेंड हैं।फरियादी युवक का नाम अमित कुमार सेन (उम्र 38 वर्ष) है। वह ग्वालियर के जनकपुरी का रहने वाला है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी के तीन से चार प्रेमी हैं।अभी वह राहुल बाथम नाम के व्यक्ति के साथ लिव-इन में रह रही है।पीड़ित पति फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठा गया।अमित ने आशंका जताई है कि मेरठ के 'ब्लू ड्रम हत्याकांड' की तरह मेरी भी हत्या करवाई जा सकती है, क्योंकि पत्नी का प्रेमी मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c

न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार,29 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

अबकी खूब तपाएगी गर्मी, दोगुने होंगे हीटवेव के दिन

● मौसम विभाग का अनुमान, सबसे गर्म साल होगा 2025 ● 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन चल सकती है लू

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल देश के नॉर्थ-वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीटवेव (लू) के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल हीटवेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना

है कि अगर हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। बीते साल देश में 554 दिन हीटवेव का असर रहा था। बता दें कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हीटवेव के लिए इन्हें गिनने का अलग तरीका है। मान लीजिए किसी महीने दिल्ली में 10 दिन, राजस्थान में 15 दिन, यूपी में 12 दिन और बिहार में 8 दिन हीटवेव रही, तो हीटवेव डे 45 (10+15+12+8) माने जाएंगे।

अधिकारी नहीं आए तो भोपाल सांसद ने मीटिंग छोड़ी

निगम कमिश्नर पर भड़के, अफसर ने सांसद, विधायक और मेयर का फोन तक नहीं उठाया

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक बैठक में नगर निगम कमिश्नर के नहीं आने से नाराज सांसद आलोक शर्मा बैठक छोड़कर चले गए। अधिकारी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। सांसद ने नगर निगम अधिकारियों के रवैये पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे भोपाल की जनता और जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। दरअसल, भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने शुक्रवार को पहली बार जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की मीटिंग ली। जिसमें बिजली कंपनी की समीक्षा के बाद एरिगेशन की समीक्षा हुई। इसके बाद नगर निगम की समीक्षा होनी थी। इसके लिए जब नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि वे नहीं है। जब पूछा कि उनकी जगह कौन आया है तो बताया गया कि कोई नहीं है। इसके बाद सांसद, महापौर और विधायक भगवान दास सबनानी ने नगर निगम कमिश्नर को फोन लगाया। लेकिन, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इससे नाराज होकर सांसद आलोक शर्मा ने बैठक स्थगित कर दी।

सांसद बोले- ये भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान सांसद आलोक सांसद ने कहा कि नगर निमग कमिश्नर का बैठक में नहीं आना भोपाल की 35 लाख आबादी का अपमान है। वे विधायक और महापौर का काल भी नहीं उठा रहे हैं।

दरअसल, बैठक में स्मार्ट सिटी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात होनी थी। बैठक में विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर बाई गुर्जर, उपाध्यक्ष मोहन जाट, सीईओ इला तिवारी समेत जिला अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कहा- कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण आज की बैठक हमने स्थगित कर दी है। शीघ्र ही जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे।

जनप्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे कलेक्टर

बैठक स्थगित होने के बाद नाराज जनप्रतिनिधियों से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मिलने पहुंचे।

बिजली कनेक्शन काटने और पानी का बड़ा मुद्दा

भोपाल के गांवों में बिजली कनेक्शन काटने और पानी का बड़ा मुद्दा था। इसी मुद्दे पर गुरुवार को हुई जिला पंचायत साधारण सभा की मीटिंग में जिपं उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य विनय मेहर, फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई थी। शुक्रवार को भी इस मुद्दे को लेकर बात हो सकती थी।

इंजीनियर पर भड़के थे जनप्रतिनिधि: गुरुवार को उपाध्यक्ष जाट, सदस्य विनय मेहर ने बिजली कनेक्शन काटने और गांवों के अंधेरे में डूबे रहने का मुद्दा उठाया था। जाट भी गांवों में पेयजल के मुद्दे पर इंजीनियर संजय सक्सेना पर भड़के थे। उन्होंने कहा था कि कई गांवों में पेयजल समस्या है, लेकिन हैंडपंप नहीं सुधारे जा रहे। ऐसा ही रवैया रहा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। उपाध्यक्ष जाट और सदस्य मेहर ने 15 दिन के अंदर पेयजल समस्या दूर करने की मांग की है।

दूसरी ओर, जनपद अध्यक्ष राजपूत बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री (ईई) पंकज यादव पर जमकर भड़के थे। बकाया राशि का हवाला देकर पूरे गांव की बिजली काटने से नाराज राजपूत ने कहा था कि कई बार मीटिंग लेकर बोला है। इसके बाद भी ईई यादव लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जवाब में कार्यपालन यंत्री पंकज यादव ने कहा था कि नियमानुसार ही कनेक्शन काट रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी

● एफआईआर वाली याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक पीआईएल पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी यह मामला शुरुआती दौर में है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्मा के आवास पर अवैध नकदी मिलने के मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई।

चीन के खिलाफ भारत और बांग्लादेश आए एक साथ

● दुनिया के सबसे बड़े बांध पर ड्रैगन बुरा फंसा

ढाका (एजेंसी)। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के विशाल बांध के विरोध में अब भारत के साथ बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर बनने वाली मेडोग जलविद्युत परियोजना के असर के बारे में चीन से विस्तार में तकनीकी जानकारी देने को कहा है। ढाका के जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पिछले महीने बीजिंग को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें चार प्रमुख दस्तावेज मांगे गए थे। इसमें पर्यावरणीय

प्रभाव का आंकलन, व्यवहार्यता अध्ययन, जलवायु प्रभाव आंकलन और आपदा प्रभाव आकलन शामिल है।

आपके लिए पुल होगा, हमारे लिए सपना है!

● बिहार की नीतिश सरकार को खटक रहा आधा-अधूरा ढांचा

पूर्णिया (एजेंसी)। जब लोगों की उम्मीद 'सर्व शक्तिशाली' सरकार से टूट जाती है तो लोग अपना सपना खुद ही पूरा करने का बीड़ा उठा लेते हैं। फिर तैयार होता है पूर्णिया के कारी कोसी नदी पुल। जब इसका ढांचा दिखने लगता है तो तोड़ने के लिए जेसीबी के साथ दर्जनभर पुलिस वालों के साथ अफसर पहुंच जाते हैं। मगर, ग्रामीणों ने अपने 'सपनों के पुल' को बचाने के लिए जी-जान से जुट जाते हैं। आखिरकार, उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। प्रशासन की टीम को लौटना पड़ता है। दरअसल, बिहार के पूर्णिया जिले में लोगों ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और पैसे से एक पुल का निर्माण शुरू कर दिया है।

यह पुल पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 (बिन टोली) के पास कारी कोसी नदी पर बन रहा है। सालों से पुल की मांग कर रहे ग्रामीणों ने जब देखा कि उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा, तो उन्होंने खुद ही यह काम करने का फैसला किया। इनका मानना है कि पुल के बनने से इलाके के किसानों को बहुत फायदा होगा, जिनकी जमीन नदी के उस पार है। ग्रामीणों ने इसके लिए एक जमींदार से जमीन ली और फिर पाई-पाई जोड़कर पुल का काम शुरू कर दिया। इस इलाके के सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ जमीन नदी के दूसरी तरफ है। वहां खेती करने के लिए जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी।

कठुआ में एनकाउंटर 5 आतंकी ढेर, चार जवान भी शहीद

कठुआ (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के राजबाग में 27 मार्च से चल रहे एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए हैं। गोलीबारी में सुरक्षाबलों के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। ये जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं। कल ये जवान

जैश के संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली जिम्मेदारी

घायल हुए थे, कल देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद जवानों में तारिक हुसैन, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह शामिल हैं। चौथे की जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जम्मू-कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के इन जवानों को पेट में गोली लगी थी। डीएसपी धीरज सिंह समेत 4 अन्य घायलों का इलाज ऊधमपुर में सेना के अस्पताल में चल रहा है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी का जमकर विरोध

● छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए, कोलकाता रेप-मर्डर पर सवाल पूछे ● ममता बोलीं-यहां राजनीति नहीं करो, यह मामला अभी अदालत में है

कोलकाता-लंदन (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में गुरुवार को भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हुई हिंसा, आरजी कर कॉलेज रेप-मर्डर केस और संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल उठाए। ममता ने कहा- आप जानते हैं कि यह मामला अदालत में है और ये केस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा, यहां राजनीति मत करो, यह राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। प्रदर्शनकारियों के हंगामे की वजह से ममता को भाषण रोकना पड़ा। यह विरोध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने किया है। छात्र संगठन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे दावों का विरोध कर रहे थे। घटना का वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल

मीडिया एक्स पर शेयर किया। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी बंगाली हिंदू समुदाय से थे। भाजपा ने इस घटना को 'बंगाल के लिए शर्मिंदगी' बताया है। पार्टी का कहना है कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया है। ममता बोलीं- भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा इवेंट के दौरान होस्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने असहमति जताई और कहा,मैं इससे अलग राय रखती हूं। इसका वीडियो शेयर करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी को भारत के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से समस्या है। यह शर्मनाक है। उन्होंने विदेशी धरती पर बैठकर संवैधानिक पद का अपमान किया है। विभाजन करना बेहद आसान, एकता बनाए रखना एक कठिन काम है, लेकिन लोगों को विभाजित करने में बस एक पल लगता है। जब मैं कुर्सी पर होती हूं तो मैं समाज को विभाजित नहीं कर सकती। मुझे कमजोर वर्गों और गरीबों का ख्याल रखना होता है। हमें उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है।

● ओला, उबर को चुनौती! ड्राइवर-राइडर दोनों का फायदा,नहीं देना होगा कमीशन

मोदी सरकार शुरू करने जा रही 'सहकार टैक्सी'

नई दिल्ली (एजेंसी)। ओला, उबर जैसी सर्विसेज के साथ अपनी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि उन्हें सही भुगतान नहीं किया जाता। तमाम ड्राइवरों को यह आरोप लगाते हुए देखा गया है कि कंपनियां उनसे ज्यादा कमीशन लेती हैं और उन्हें कम पेमेंट होता है। ओला-उबर को अब एक नई चुनौती मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार बहुत जल्द 'सहकार टैक्सी' नाम से एक नई टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर मिलेगी। इस सर्विस के तहत लोग बाइक, कैब और ऑटो बुक करा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 'सहकार टैक्सी' का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ड्राइवरों को बड़ी कंपनियों को मुनाफा दिए बिना सीधे कमाने में मदद करना है। कहा जा रहा

है कि किसी राइड से जो भी मुनाफा होगा, वह सीधे ड्राइवर को मिलेगा। उसे कहीं कोई कमीशन नहीं देना होगा। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में सहकार टैक्सी पूरे देश में शुरू हो जाएगी। इस सर्विस से होने वाला सारा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा। एक सहकारी बीमा कंपनी भी बनाई जाएगी, जो बीमा सेवाएं देने का काम करेगी। बताया जा रहा है कि सर्विस से जुड़ने के लिए टू वीलर और फोर वीलर्स का रजिस्ट्रेशन सहकार टैक्सी में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सर्विस से जो भी मुनाफा होगा, वह किसी बिजनेसमैन की जेब में नहीं जाएगा। वह सीधे गाड़ी चलाने वाले को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, सहकार टैक्सी का मुख्य मकसद लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया कराना है। इससे ड्राइवरों को कमाई करने के बेहतर विकल्प मिलेंगे। एक सहकारी बीमा कंपनी भी बनाई जाएगी, जो बीमा सेवाएं देने का काम करेगी।

तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित

● सीएम स्टालिन बोले- केंद्र बिल वापस ले,ये मुसलमानों के अधिकार खत्म करेगा

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रस्ताव के विरोध में कहा- ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिल वापस ले। स्टालिन ने कहा कि, केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ हैं। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा- संशोधन में कहा गया है कि दो गैर मुस्लिम लोग को वक्फ का हिस्सा होना चाहिए। मुसलमानों को डर है सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है।

15 बड़ी मस्जिदों पर विशेष सुरक्षा,15 सौ पुलिसकर्मी संभालेंगे व्यवस्था

भोपाल (नप्र)। ईद और गुड़ी पड़वा पर पूरे शहर में विशेष सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया कि त्यौहार के दिन शहर में 1500 जवान सुरक्षा जिम्मा संभालेंगे। ईद के लिए शहर की 15 बड़ी मस्जिद चिह्नित हैं। यहां विशेष सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। जरूरत पड़ने पर पुलिस ड्रोन उड़ाएगी। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी कार्रवाई की जाएगी।

गुड़ी पड़वा 31 मार्च की है, लेकिन ईद का दिन तय नहीं है। चांद दिखने के बाद ही ईद होगी। लिहाजा ईद 31 मार्च या एक अप्रैल की हो सकती है। प्रत्येक थाने में मोबाइल टीमें गश्त पर रहेंगी। त्योहार से पहले विशेष अभियान चलाकर गुंडे-बदमाशों पर कार्रवाई की जाएगी। चाकूबाजों पर पुलिस की नजर है। इन सभी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

थानावार समीक्षा हुई- गुरुवार को क्राइम मीटिंग में थाना वार समीक्षा हुई। क्राइम कंट्रोल के लिए थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसकी समीक्षा की। वारंट तामीली से लेकर गंभीर अपराधों में कार्रवाई कैसी रहेगी। इसकी जानकारी ली। पेंडेंसी का जल्द निकाल करने के निर्देश दिए।

गंदा पानी सड़क पर बहाने पर चार पर स्पॉट फाइन

भोपाल (नप्र)। नल से पीने के पानी से घर धोने पर नगर निगम ने चार लोगों के खिलाफ 2 हजार रुपए स्पॉट फाइन लगाया। यह कार्रवाई तुलसी विहार कालोनी अवधपुरी में की गई। निगम के अनुसार दिलीप पुट्टी, राजेन्द्र कुमार यादव, दिनेश कुमार सिंह एवं मुकेश कुमार शर्मा अपने मकान को धोकर गंदा पानी सड़क पर बहा रहे थे। निगम की समझाइश के बाद भी ये लोग पानी सड़क पर बहाकर गंदगी फैला रहे थे। इन पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए 500 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना लगाया गया।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2025 में मप्र का उम्दा प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक दिल्ली में किया गया। इसमें मध्यप्रदेश के पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन टेबल टेनिस में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने उम्दा

प्रदर्शन किया। वूमेन क्लास 10 वर्ग में दिव्यानी वाल्हे ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि पुरुष क्लास-08 वर्ग में गजानन परमार ने रजत पदक जीता। इसके अलावा, पुरुष क्लास-07 केटेगरी में हर्ष त्रिवेदी ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

खेल मंत्री ने दी बधाई

प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश के पैरा खिलाड़ियों के साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के खेल क्षेत्र के विकास और खिलाड़ियों की मेहनत का प्रमाण है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मध्यप्रदेश की टीम ने 6 पदक (3 स्वर्ण, 3 रजत) जीते थे, जबकि इस वर्ष 2025 में खिलाड़ियों ने 11 पदक (3 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य) जीतकर प्रदेश के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है।

भोपाल में काजी बोले-

वक्फ संपत्तियों पर जालिम की नजर

● जायदादों को हड़पकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की प्लानिंग

भोपाल (नप्र)। भोपाल में रमजान महीने के आखिरी जुमे पर मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण और मौन विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। बोर्ड ने कहा कि अगर यह बिल पारित हो गया तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और कई अन्य संस्थान उनके हाथ से चले जाएंगे।

इस मौके पर भोपाल के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में ताजुल मसाजिद में हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। काजी सैयद अनस अली ने बताया कि वक्फ अमेंटमेंट बिल वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है। यह बिल मुस्लिमों के हित में नहीं है।

सुनियोजित तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने और मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए यह बिल है। वक्फ की संपत्तियों पर जालिमों की नजरें हैं। यह जालिम हमारी संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम अपनी संपत्तियों की हिफाजत हर हाल में करेंगे।

सुरक्षा पर सवाल!

कटारा हिल्स में संदिग्धों की घुसपैठ,रात के अंधेरे में घर में घुसने की कोशिश

भोपाल (नप्र)। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चोरी और संदिग्ध गतिविधियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 27 मार्च की रात कस्तूरी कॉलोनी में कुछ संदिग्ध लोग एक घर में घुसने की कोशिश करते दिखे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका 2 मिनट 28 सेकेंड का वीडियो सामने आया है।

रात 3.05 बजे घर में घुसने की कोशिश- वीडियो में दिख रहा है कि रात 3:05 बजे कुछ लोग एक घर के गेट के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। हालांकि, वे घर में दाखिल नहीं हो सके और कुछ देर बाद वहां से चले गए। इससे पहले भी बाग मुगालिया एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों में कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है।

कॉलोनीवासियों में चिंता, सुरक्षा बढ़ाने की मांग- लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कॉलोनीवासियों में डर का माहौल है। बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई संदिग्ध लोग देर रात कॉलोनी में घूमते रहते हैं, जिससे चोरी के साथ-साथ जनहानि की आशंका बनी हुई है।

प्रदेश के शिवपुरी में लू, खजुराहो में पारा 41.4 डिग्री

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में इस सीजन में पहली बार शिवपुरी में लू का असर देखा गया। यहां दिन का पारा 40.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से ज्यादा था। इस वजह से हीट वेव चली। वहीं, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल में सामान्य तापमान 2.5 डिग्री से अधिक रहा।

छतरपुर के खजुराहो में सीजन में पहली बार गुरुवार को पारा 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, ग्वालियर और जबलपुर में 40 डिग्री के आसपास रहा। दमोह, गुना, शिवपुरी, सतना और सागर ऐसे शहर रहे, जहां 40 डिग्री या

इससे अधिक दर्ज किया गया। हालांकि, अगले 2 से 3 दिन तक पारे में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं की वजह से पिछले 3 दिन से तापमान में खासी बढ़ोतरी हुई है। निवाड़ी का पृथ्वीपुर और छतरपुर का खजुराहो सबसे गर्म है। शुक्रवार से कुछ शहरों में पारे में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, सुबह से सूरज के तेवर तीखे देखने को मिल रहे हैं। भोपाल में सुबह से ही गर्मी का असर है।

इन शहरों में गर्मी का असर ज्यादा

मौसम विभाग के अनुसार, कई शहरों में गर्मी का असर देखा गया। खजुराहो (छतरपुर) में 41.4 डिग्री, दमोह में 40.5 डिग्री, गुना, सतना-शिवपुरी में 40.2 डिग्री और सागर में पारा 40 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह मंडला-टीकमगढ़ में 39.8 डिग्री, नर्मदापुरम में 39.6 डिग्री, रीवा में 39.4 डिग्री, शाजापुर में 39.3 डिग्री, सिवनी में 38.8 डिग्री, उमरिया में 38.7 डिग्री, मलाजखंड में 38.5 डिग्री, सीधी, धार-खरगोन में 38.4 डिग्री, बैतूल-रतलाम में 38.2 डिग्री, खंडवा में 38.1 डिग्री, नरसिंहपुर-नौगांव में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 38.7 डिग्री, इंदौर में 37.6 डिग्री, ग्वालियर में 39.5 डिग्री, उज्जैन में 38 डिग्री और जबलपुर में पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सामान्य से ज्यादा पारा

पिछले 3 दिन से प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ा है। दिन में तीखी धूप खिल रही है। इस कारण लोग बचने के तरीके ढूंढते हैं। दूसरी ओर, कई शहरों में पारा सामान्य से 1 डिग्री से 4.5 डिग्री तक अधिक है।

5.50 लाख पेंशनर्स की डीआर अटकाई

भोपाल (नप्र)। मप्र के 5.50 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने में देरी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ से सहमति लेने में देरी के कारण पेंशनरों को 14 महीने की डीआर का नुकसान हुआ। इस मामले में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मप्र के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को 5000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। 3 दिन पहले (24 मार्च को) सिंगल बेंच में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया।

छग से दो बार में मिल सकी सहमति- संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद्र वर्मा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया। वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से डीआर के लिए मप्र सरकार ने छग से सहमति मांगी थी, लेकिन छग सरकार ने इसे 6 महीने बाद 1 जुलाई 2023 से मंजूरी दी। फिर 1 जुलाई 2023 से डीआर के लिए मप्र सरकार ने दोबारा सहमति मांगी, जिसे छग ने 1 मार्च 2024 से दी। इस देरी से पेंशनरों को डीआर का नुकसान हुआ।

पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया, लेकिन लागू नहीं हुआ- पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया, लेकिन लागू नहीं हुआ : वर्मा ने छग के वित्त सचिव को चिट्ठी लिखकर पूछा कि देरी के लिए उनके खिलाफ अभियोजन क्यों न दायर किया जाए।

इस पर जवाब नहीं मिला तो इंदौर बेंच में याचिका दायर की। 30 जुलाई 2024 को पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया।

सीएम से विश्व विख्यात बिजनेस कंसलटेंट डॉ. रामचरण ने भेंट की

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से विश्व विख्यात बिजनेस कंसलटेंट, लेखक तथा वक्ता डॉ. रामचरण ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. रामचरण को प्रदेश में व्यवसाय अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, प्रदेश को वैश्विक व्यापार मंचों पर आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने

और वैश्विक स्तर पर प्रदेश की निवेश क्षमता के प्रदर्शन के लिए जारी गतिविधियों से अवगत कराया। प्रदेश में लॉजिस्टिक हब, स्मार्ट औद्योगिक पार्क, स्टार्ट-अप इको सिस्टम, ए.आई., ऑटोमेशन, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ।

डॉ. रामचरण, कॉरपोरेट गवर्नेंस, व्यावसायिक प्रबंधन और तेजी से बदलते वर्तमान परिवेश में व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें फॉर्च्यून पत्रिका ने सबसे प्रभावशाली सलाहकार और इकोनामिक टाइम्स ने वर्ष 2010 के लिए ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर नामित किया है।

जिला पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों का हंगामा

पानी की सप्लाई पर अफसरों से भिड़े उपाध्यक्ष, धरने पर बैठने की धमकी

भोपाल (नप्र)। करीब 4 महीने बाद हुई जिला पंचायत की बैठक में जमकर बहसबाजी हुई। हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी सप्लाई होने के मुद्दे पर पीएचई अधिकारी बीच में खड़े होकर बोलने लगे। इस पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन जाट ने कहा- आप ही सभी अधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं। कहीं पानी सप्लाई नहीं हो रहा।

इस बात पर दोनों में तनातनी हो गई। मामला बढ़ता देख जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और विधायक प्रतिनिधि को बीच-बचाव करना पड़ा। बैठक में 17 बिंदुओं पर एजेंडा रखा गया था। जाट ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं हुए, तो मैं खुद ही अकेले हड़ताल पर बैठूंगा।

बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने मीडिया को बाहर जाने के लिए कहा तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आपत्ति ली।

बैठक के दौरान ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई का मुद्दा उठा। हैंडपंप सूखने की बात पर पीएचई की कार्यपालन यंत्री जवाब देने लगीं, लेकिन उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी पीएचई के इंजीनियर संजय सक्सेना उठकर बोलने लगे। जाट ने कहा- कहीं पानी नहीं सप्लाई हो रहा है।

बिजली कंपनी के ईई से भिड़े जनपद पंचायत अध्यक्ष- बैठक में बिजली कंपनी के ईई पंकज यादव और फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत के बीच विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि आप बकाया राशि का हवाला देकर पूरे गांव की बिजली काट देते हैं। यह क्या तरीका है। बैरसिया सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी होने का मुद्दा भी उठाया गया।

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति, वन, महिला बाल विकास समेत 15 विभाग के कामों की समीक्षा हुई। इससे पहले सामान्य प्रशासन समिति की मीटिंग भी हुई, जिसमें प्रतिनिधियों को एंट्री नहीं दी गई।

गुस्से में उठकर उपाध्यक्ष के पास पहुंचे इंजीनियर

जिपं उपाध्यक्ष की बात सुनकर इंजीनियर सक्सेना गुस्से में उठकर उपाध्यक्ष जाट के पास पहुंचे। बैठक में विधायक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर के बेटे बीच-बचाव करने पहुंचे। उसके बाद भी जमकर हंगामा हुआ। गांव में पानी, सड़क को लेकर सदस्य मेहर, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने भी विरोध जताया। कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है। हर बार ऐसा ही रवैया रहा है। यही स्थिति रही तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।

आईएएस नियाज खान बोले-ब्राह्मण 'सुपर जीनियस'

ट्वीट कर कहा देश में नफरत का माहौल, इसे ब्राह्मण ही खत्म कर सकते हैं

भोपाल (नप्र)। 'ब्राह्मण द ग्रेट' नॉवेल लिखकर सुर्खियां बटोर चुके आईएएस अफसर नियाज खान ने अपने हालिया बयान में कहा है कि ब्राह्मण समाज को अलग-थलग रखना देश के लिए अपार हानि का कारण बन सकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को यहूदियों की तरह 'सुपर जीनियस' बताते हुए कहा कि जैसे ही वह ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है।

नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- देश में हर तरफ नफरत का माहौल है, जिसे केवल ब्राह्मण ही ठीक कर सकते हैं। उनके मुताबिक, एक ब्राह्मण अकेला कई हजार के बराबर होता है। इतिहास भी ब्राह्मणों ने ही बदला था। ब्राह्मण देश के केंद्र बिंदु हैं और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए नफरत खत्म होना जरूरी है। ब्राह्मणों को आगे आकर इसे खत्म करना चाहिए।

- **नफरत फैलाने वाला खुद का ही विनाश करता है-** नफरत के

खिलाफ अपनी बात रखते हुए खान ने लिखा- सनातन धर्म प्रेम, उदारता और सदाचार पर आधारित है। जो नफरत फैला रहे हैं, वे सनातनी नहीं हो सकते।

- **हिंदू धर्म में प्रकृति का सम्मान सबसे अधिक-** खान ने एक अन्य पोस्ट में हिंदू धर्म को प्रकृति के सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने लिखा, चारों वेद प्रकृति पर केंद्रित हैं। हिंदू धर्म में सदियों से पेड़ों, नदियों और हरियाली को महत्व दिया गया है, जबकि अन्य धर्मों में इसका अभाव रहा है। धरती को विनाश से बचाने के लिए भारत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है।
- **राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता जरूरी-** उन्होंने वैश्विक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज दुनिया में पावर की होड़ लगी हुई है। अमेरिका और चीन लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भारत को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। खान ने अपील की कि समाज को नफरत फैलाने वालों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

हनुमान जयंती मेले के लिए स्पेशल ट्रेन

भोपाल (नप्र)। हनुमान जयंती मेला 2025 के अवसर पर यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल द्वारा भोपाल-इटावा-भोपाल अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन (01601/01602) चलाई जा रही है।

इस विशेष ट्रेन का संचालन कुल 7 फेरे में किया जाएगा। यह ट्रेन भोपाल से 30 मार्च, 01, 3, 5, 7, 10 एवं 12 अप्रैल 2025 को और इटावा से भी इन्हीं तारीखों पर चलाई जाएगी।

चैत्र नवरात्रि 2025 में विशेष संयोग

सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी मां दुर्गा की आराधना, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक रखें व्रत

भोपाल (नप्र)। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ एक विशेष संयोग में होने जा रहा है। नववर्ष गुड़ी पड़वा के दिन 30 मार्च को सूर्योदय के साथ मीन लग्न में माता रानी का आगमन होगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थसिद्धि योग में हो रही है, जो इसे और भी खास बना रहा है।

रविवार के दिन माता रानी ऐरावत हाथी की सवारी पर विराजमान होकर भक्तों के घर-आंगन में पधारेंगी। पहले दिन घटस्थापना, पूजा-संकल्प और व्रत संकल्प के लिए ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर का अभिजीत काल विशेष शुभ माना गया है।

ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. विनोद गौतम ने बताया कि कुछ पंचांग कैलेंडरों के अनुसार एक तिथि क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिन की बताई जा रही है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत 9 दिन तक ही रखना चाहिए। अगर कोई व्रतधारी 8वें दिन व्रत तोड़ता है, तो पूरा व्रत खंडित माना जाएगा।

विशेषज्ञों की सलाह है कि भक्तों को 30 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरे 9 दिन का व्रत रखना चाहिए। तिथियों में कमी होने के बावजूद नवरात्रि का अनुष्ठान पूरे 9 दिन का ही करना चाहिए। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजा और अनुष्ठान का पूर्ण विधान से पालन करना आवश्यक है।

संपादकीय

अवकाश पर उठ रहे कई सवाल

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा इस बार राज्य में ईदुल फितर की सरकारी राजपत्रित छुट्टी रद्द कर उसे रस्ट्रीक्टेड (सीमित) अवकाश में बदलने के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सैनी सरकार ने इस बदलाव के पीछे जो तर्क दिए हैं, वो शायद ही किसी के गले उतरें। क्योंकि संविधान की सर्व धर्म समभाव की मूल भावना के तहत देश में सभी धर्मों के प्रमुख त्यौहारों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गजेटेड छुट्टियां रहती आई हैं तथा इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। ईदुल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हरियाणा में भी करीब 7 फीसदी आबादी मुसलमानों की है। इनमें से भी ज्यादातर नूह जिले में रहते हैं। हरियाणा राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश में इस दिन शासकीय अवकाश रहता आया है। यह देश में पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय अवकाश को किसी राज्य ने सीमित अवकाश में बदलने का काम किया है। इससे राज्य सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-2 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के पीछे तर्क दिया गया है कि चूंकि इस साल मार्च के अंत में लगातार तीन दिनों तक छुट्टियां पड़ रही हैं, जिनमें 31 मार्च को ईदुल फितर का त्यौहार भी शामिल है, इससे वित्तीय वर्ष समापन का कार्य प्रभावित होगा। 31 मार्च को ईयर क्लोजिंग है। इसलिए ईद की छुट्टी को सीमित अवकाश में तब्दील किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ईद पर अब केवल मुस्लिम ही छुट्टी ले सकेंगे। बाकी लोगों को काम पर आना होगा। हालांकि यह आदेश केवल इसी साल के लिए है या फिर स्थायी रूप से लागू होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अगर संख्या बल के आधार पर ही देश में छुट्टियां हो तो ज्यादातर राज्यों में केवल हिंदुओं और चुनिंदा राज्यों में मुस्लिम, ईसाई, सिख अथवा बौद्धों के हिसाब से ही छुट्टियां होंगी। जैन धर्म के तो किसी भी त्यौहार पर अवकाश नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी राज्य में प्रभावी संख्या, में नहीं है। पारसी त्यौहार पर अभी केवल महाराष्ट्र,गुजरात में ही छुट्टी होती है, जबकि यहूदियों के त्यौहार पर कोई अवकाश नहीं होता, क्योंकि उनकी संख्या नगण्य है। हरियाणा में जो हो रहा है, वह पाकिस्तान की तरह है, जहां हिंदू, ईसाई अल्पसंख्यकों के त्यौहारों पर सीमित अवकाश ही रहता है। जहां तक हरियाणा सरकार का मार्च एंड का तर्क है तो वह बोदा है। वित्तीय वर्ष का समापन अकेले हरियाणा में नहीं है, वह पूरे देश, सभी बैंकों व वित्तीय तंत्र से जुड़ा है। इसके बाद भी ईद की छुट्टी राष्ट्रीय छुट्टी है। क्या हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की छुट्टी की भी अवहेलना करना चाहती है? या फिर हरियाणा में मुसलमानों के त्यौहारों की सभी छुट्टियां रद्द करने का यह कोई पायलेट प्रोजेक्ट है, जिसे पहले हरियाणा में आजमाया जा रहा है। नतीजे देखने पर पूरे देश में मुसलमानों के सभी त्यौहारों पर यह कहकर छुट्टियां खत्म की जाएंगी कि यह 18 फीसदी लोगों का त्यौहार है, इसलिए बाकी सभी लोग छुट्टी पर रहने की बजाय काम करें। वैसे भी निजी क्षेत्र में हिंदुओं के कुछ बड़े त्यौहारों के अलावा बाकी पर्वों पर पूरी तरह काम बंद नहीं होता। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो यह संविधान की उस भावना के विपरीत होगा, जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, बावजूद इसके कि कौन सा पर्व कितने लोग मनाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन करने का उपयुक्त समय

नजरिया

डॉ. मनीष जैसल

लेखक जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में सहायक प्रोफ़ेसर

देश की शिक्षा व्यवस्था में वर्षों बाद एक बदलाव की शुरुआत 2020 में की गई। जिसे नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर जाना जाता है। करीब पांच वर्षों के संदर्भ में इसे देखें तो देश के लाखों स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इस नीति को शामिल करने की बात कही जा रही है। लेकिन इससे देश में क्या बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं इसको लेकर बीते मंगलवार को राज्य सभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार लगातार शिक्षा बजट को घटा रही है। 2015-16 में यह 3.8 प्रतिशत था, जो 2025-26 तक 2.5 प्रतिशत रह गया है। इसलिए इन सवालों से मुँह नहीं फेर जा सकता।

दरअसल देश में चल रही पुरानी शिक्षा व्यवस्था की जिन खामियों को ध्यान में रखकर सरकार ने बदलाव किए थे उस पर संसद में कोई बहस नहीं हुई, यह सवाल विपक्ष आज भी उठाता है। अब जब देश में यह पूरी तरह लागू हो चुकी है तो इनके परिणाम पर भी बातचीत होना लाज़मी है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। उसी को ध्यान में रखकर हम इस मुद्दे को देखने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण से समझें तो एक ओर जहां मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ावा देने की बात यह शिक्षा नीति कहती है। लेकिन जिस भाषा में आप मेडिकल, क़ानून, पत्रकारिता, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई करवाने जा रहे हैं, उससे जुड़ी किताबों और रेफ़्रेंस को लेकर सरकार का क्या रूख है यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक छात्र जो हिंदी या किसी अन्य भाषा में पाठ्यक्रम में नामांकन ले चुका है उसके पास कितने विकल्प है उस माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने के यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मातृभाषा में पुस्तकों का लेखन कार्य देश में उस स्तर पर आरम्भ नहीं हुआ जिससे इस कमी को समय रहते पूरा किया जा सके। चूँकि लेखन में समय लगता है इसलिए कठिन विषयों को मातृभाषा में अगर छात्र पढ़ सकेंगे तो उनमें विषय और पाठ्यक्रम को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जिसका फ़ायदा उन्हें रोज़गार पाने में ज़रूर मिलेगा।

दूसरा सवाल इसी से निकल कर सामने आता है कि जिस शिक्षा नीति में विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है वहां सन् 2022-23 और 23-24 में पहली से आठवीं कक्षा के क़रीब 54,77,223 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं। इसके कारण पर सरकार का क्या रूख है इसे भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है। उधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के इस सवाल से भी सहमत हुआ जा सकता है कि यह शिक्षा नीति 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ बनाने का लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन इसके लिए शिक्षा और महिला एवं बाल विकास में अब तक ठीक समन्वय क्यों नहीं बैठ सका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए स्कूल खोलने का लक्ष्य तब किताबी सा लगने लगता है जब

मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में 30 हज़ार स्कूल बंद कर देने और उनके प्राइवेट स्कूल में जाने पर मजबूर होने की ख़बरें आने लगती हैं। ऐसे में एनईपी 2020 के तहत एचएचआरओ द्वारा जिस 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था और वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किए जाने की बात थी इसका मूल्याँकन अब ज़रूरी है। बात युवाओं की करें तो स्कूल से निकल कर एक छात्र जब स्नातक की पढ़ाई के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है और उसे यह शिक्षा नीति मल्टीपल एंट्री एक्ज़िट का ऑप्शन देती है। इस ऑप्शन के असर पर भी सरकार को एक बार ग़ौर करना चाहिए क्योंकि हाल ही में राज्यसभा में कॉंग्रेस की रीताव्रता बनर्जी ने जो मुद्दा उठाया जो अहम है। उन्होंने कहा कि देश के 80 फ़ीसदी युवा बेरोज़गार हैं। चूँकि यह नयी शिक्षा नीति रोज़गार के सृजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देती है ऐसे में बेरोज़गारी का यह आँकड़ा हमें चौंका सकता है। हमें इस ओर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत कि देश में मात्रा 13 प्रतिशत शिक्षक ही प्रशिक्षित हैं। उनके प्रशिक्षण में होने वाली देरी इन नीति के क्रियान्वयन और असर पर भी प्रभाव डालेगा। राज्यसभा में सांसद सुधा मूर्ति का तर्क स्वागत योग्य माना जा सकता है जिसमें वें प्राथमिक और उच्च शिक्षा से जुड़े अध्यापकों के लिए हर तीन साल में ट्रेनिंग और उसकी परीक्षा का सुझाव दिया।

नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये ख़ास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाए जाने की बात थी उस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी अब तक नहीं आ सकी है। दूसरी ओर देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना की बात हुई थी। उस फंड के इस्तेमाल की जानकारी पर भी सरकार को आधिकारिक टिप्पणी करनी चाहिए। हालाँकि भाजपा के घनश्याम तिवारी ने दावा किया कि भाजपा सरकार के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम दस सालों में हुआ है, उतना उससे पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति से भारत अनुसंधान और शिक्षा का उसी प्रकार का विश्व केंद्र बन जाएगा जैसे प्राचीन काल में नालंदा हुआ करता था। लेकिन यहां यह भी ग़ौरतलब है कि 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना था वहां बच्चों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग होना नए सवाल खड़े करता है। वहीं निजी हाथों में शिक्षा व्यवस्था कर बढ़ना भविष्य के लिए संकट खड़े कर सकता है। वहीं यह नीति जिस स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि की बात कर रही थी वहां देश में बेरोज़गारी के आँकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। नए विषयों के बढ़ावे के साथ साथ नई चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं। एआई के आने से डीप फेक से बचने की चुनौती को हम सब झेल ही रहे हैं।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गयी नई शिक्षा नीति को लेकर कई चुनौतियां पहले भी आंकी गयी थी। लेकिन देश के सभी राज्यों ने इसे समय रहते अपनाया। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफा खोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर शिक्षा के जिस संस्कृतिकरण की चिंता जताई जा रही थी वह संकट अब भी बना हुआ है। दक्षिण के प्रदेशों के बीच बीच में ऐसी ख़बरें हम सुनते ही रहते हैं। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने एवं सिखाने की क्रिया। समाज में इसके व्यापक अर्थ को लेकर समझे तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर स्वयं को योग्य नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर सकता है। देश की सरकार ने भी ऐसा ही एक सपना देखा होगा, शिक्षा के ज़रिए विकसित राष्ट बनने का। अब समय है इस बदलाव की प्रकिया को थोड़ा रूक कर जांच परख लेने का, इसकी खूबियों और खामियों पर विस्तार से बात कर लेने का। चूंकि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। इसमें गुरुर की तो गुंजाइश बचती ही नहीं। 1986 की शिक्षा नीति में पहले 1992 में संशोधन हुए फिर 2020 में जो बदलाव किए गए उसको युद्ध स्तर पर आकर जांचने और परखने की ज़रूरत है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ज़रिए समाज को शिक्षित करने का जो सपना लेकर सरकार आई थी उसमें एक दृष्टि से देखने के बजाय विविधता की ओर बढ़कर छात्रों को समझाने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी की पुस्तकों पर हो रहे बदलाव से किसी को कोई दिक़्क़त परेशानी हो या ना हो लेकिन उस एक प्रक्रिया से ज़रूर सबको परेशानी होगी जब हमारे पास सोचने और उसे समझने का सिर्फ़ एक ही रास्ता दिखेगा। दरअसल विद्यार्थी को विविधताओं से पूर्ण होता है। उसे कुंजी पढ़कर योद्धा बनाने के बजाय पूरी स्थिति को सामने रखकर उसे स्वविवेक का इस्तेमाल करने वाला विद्यार्थी बनाना होगा। तब आकर वह स्वयं अपनी संस्कृति सभ्यता और देश को दुनियां के अलग मंचों पर उस आत्मविश्वास से रख पाएगा जिसका सपना हम सबने यानी 140 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों ने देखा है। डॉ अम्बेडकर सही कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा दहाड़ेगा और वह एक दिन आएगा जब हम विकसित राष्ट्र अपनी शिक्षा के बल पर बनेंगे और उसमें नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा।

लुप्त होती हरियाणा की अनमोल विरासत रागनी कला

कला संस्कृति

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक शोधार्थी हैं।

हरियाणा की लोकसंस्कृति में रागनी एक महत्वपूर्ण कला है, जो समय के साथ धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम रही है, बल्कि सामाजिक संदेश देने, वीर रस जगाने और लोक इतिहास को संजोने का एक प्रभावशाली ज़रिया भी रही है। हरियाणा की रागनी न केवल मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम रही है, बल्कि समाज सुधार की दिशा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह लोककला सिर्फ़ संगीत नहीं, बल्कि एक आंदोलन रही है, जिसने लोगों को जागरूक किया, बुराइयों के खिलाफ खड़ा किया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हरियाणवी रागनी लोकसंस्कृति का अभिन्न अंग रही है और इसके प्रचार-प्रसार में जाहरवीर कल्लू खां, अजीत सिंह गोरखपुरिया, दयाचंद लांबा, राजेंद्र खड़खड़ी, जसमेर खरकिया, सुरेंद्र भादू, सूरजभान बलाली, मामन खान, सतीश ठेठ, कविता कसाना के साथ-साथ और भी कई महान कलाकारों का योगदान रहा है। आज भी कई युवा कलाकार रागनी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे डिजिटल मंचों के माध्यम से नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणवी रागनी को जीवित रखने में संदीप सरगथलिया, वीर सिंह फौजी, धर्मवीर नागर, राजबाला, मास्टर छोटूराम बड़वा जैसे कई कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी मेहनत और समर्पण से यह लोककला आज भी जीवित है, हालाँकि इसे और संरक्षण और प्रोत्साहन की ज़रूरत है।

रागनी हरियाणवी लोकगीतों और कविताओं का एक विशिष्ट रूप है, जिसे मुख्य रूप से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गाया जाता है। इसमें वीरता, प्रेम, भक्ति, सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। पहले यह कला अखाड़ों और मेलों में बहुत लोकप्रिय थी, जहाँ गायक अपनी आवाज़ और जोश के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। रागनी के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और समानता पर ज़ोर दिया गया। कई लोकप्रिय रागनियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिलाओं पर अत्याचारों का विरोध किया गया है। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' जैसे संदेशों को रागनी ने जन-जन तक पहुँचाया। हरियाणवी समाज में जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने और समानता का संदेश देने में रागनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई प्रसिद्ध रागनियों ने बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और कर्म को जाति से ऊपर रखना चाहिए। रागनी के माध्यम से शराब, जुए और अन्य नशों की लत से बचने के संदेश दिए गए। कलाकारों ने

इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रेरक गीत गाए। उदाहरण: 'सुणले रे छोरे, बीड़ी-सिगरेट मत पीजा, तन्ने मां-बाप सूँ किट्टे तै प्यारा' (एक रागनी जिसमें धूम्रपान के नुक़सान बताए गए हैं)। हरियाणा की ग्रामीण जनता के लिए रागनी एक ताकत बनी। इसमें किसानों की समस्याओं, मजदूरों के अधिकारों और सरकार से उनकी माँगों को जोरदार तरीके से उठाया गया। उदाहरण: कई रागनियों में किसान आंदोलनों, फ़सल के सही दाम और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं।

ब्रिटिश राज के दौरान रागनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रभावशाली हथियार बनी। लोकगायक अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता में देशभक्ति की भावना भरते थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान करते थे। आज के दौर में भी रागनी समाज सुधार का माध्यम बनी हुई है। डिजिटल मीडिया और मंचों पर युवा कलाकार सामाजिक मुद्दों पर रागनी प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाणवी लोकसंस्कृति की पहचान रागनी समय के साथ लुप्त होती जा रही है। कभी गाँवों के चौपालों, मेलों और अखाड़ों में गूँजने वाली यह कला अब केवल कुछ पुराने कलाकारों और रसिकों तक सीमित रह गई है। इसके लुप्त होने के पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारण ज़िम्मेदार हैं। पहले के समय में गाँवों में बैठकर बुज़ुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को लोकगीत और रागनी सिखाते थे, लेकिन अब यह परंपरा समाप्त हो रही है। लोकगीतों और रागनी को नयी शैली में ढालने का प्रयास कम हुआ है, जिससे यह लोगों के लिए कम प्रासंगिक हो गई है। नवीन मनोरंजन साधनों टीवी, इंटरनेट और पॉप संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी लोककला से दूर होती जा रही है। आधुनिक संगीत उद्योग में रागनी को वह स्थान नहीं मिला जो अन्य संगीत शैलियों को मिला है। युवा पीढ़ी इसे करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित नहीं हो रही है। इस कला को संरक्षित करने के लिए कोई औपचारिक संस्थान या पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं।

रागनी को नए संगीत वाद्ययंत्रों और आधुनिक ध्वनि तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि यह युवाओं को भी आकर्षित कर सके। हरियाणवी फ़िल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में रागनी को स्थान दिया जाए। रागनी को रैप और हिप-हॉप जैसी आधुनिक शैलियों के साथ मिलाकर फ्यूज़न रागनी तैयार की जाए, जिससे यह युवाओं तक प्रभावी रूप से पहुँचे। हरियाणवी लोकसंस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग रागनी आज विलुप्ति के कगार पर है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों के आगमन और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण यह कला पिछड़ती जा रही है। यदि समय रहते इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को यह विरासत केवल किताबों में ही देखने को मिलेगी। स्कूलों और कॉलेजों में रागनी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि युवा पीढ़ी इसकी जड़ों से जुड़ सके। विश्वविद्यालयों में लोककला और संगीत की पढ़ाई के अंतर्गत रागनी पर शोध को बढ़ावा दिया जाए। बच्चों को पारंपरिक संगीत में रुचि दिलाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। सरकार और सांस्कृतिक संस्थानों को लोक महोत्सवों में रागनी को विशेष स्थान देना चाहिए। यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे युवाओं तक पहुँचाया जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में रागनी की शिक्षा दी जानी चाहिए। लोक कलाकारों को आर्थिक और सामाजिक समर्थन दिया जाना चाहिए।

रागनी केवल एक गीत शैली नहीं, बल्कि हरियाणा की संस्कृति की पहचान है। यदि इसे संरक्षित करने के लिए उचित क़दम नहीं उठाए गए, तो यह अमूल्य धरोहर धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है कि हम इसे फिर से लोकप्रिय बनाएँ और इसकी समृद्ध परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। रागनी केवल लोकगायन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम है। यह सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने, सुधार की ओर प्रेरित करने और बदलाव लाने की ताकत रखती है। अगर इसे सही दिशा में प्रोत्साहित किया जाए, तो यह समाज सुधार की एक मज़बूत नींव बन सकती है। 'रागनी सिर्फ़ गीत नहीं, ये समाज की आवाज़ है!', 'लोककला हमारी पहचान है, इसे बचाना हमारी शान है!'

हम जमाने से हैं या जमाना हमसे है...

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

कभी बुजुर्गों से सुना करते थे कि उनके दौर में 'आंख की शरम' भी कोई चीज होती थी। जिसके चलते व्यक्ति अपने आचार विचार और व्यवहार में अत्यंत शालीनता का परिचय दिया करता था। उम्र और अनुभव के लिहाज का भरपूर खयाल रखा जाता था। शिक्षण संस्थानों में लौकिक शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा को भी वरीयता दी जाती थी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संस्कारों से परिपूर्ण होकर व्यक्ति समाज का अंग बनता था। जिसके चलते समाज और राष्ट्र के नैतिक और चरित्रिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ करता था। लेकिन वर्तमान दौर में भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति भाव इतना प्रबल हो गया है कि व्यक्ति की सफलता का पैमाना काफी हद तक आर्थिक हो गया है।

वैसे यह सच है कि अब जीवन जीना बहुत आसान हो गया है। कई मामलों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं, रहन सहन के स्तर में वृद्धि हुई है, गंभीर से गंभीर बीमारियों की भी रोकथाम होने लगी है और तमाम तरह के आंकड़े हमारी तरक्की के गीत गाते हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी आदि-अनादिकालीन सभ्यता और संस्कृति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिवंगत महापुरुषों का गलत तरीके से चरित्र चित्रण किया जा रहा है, यही नहीं अपितु वैश्विक परिदृश्य में राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते मातृभूमि के मान सम्मान और स्वाभिमान की भी परवाह नहीं की जा रही है। और तो और देवत्व को प्राप्त विभूतियों के प्रति निष्ठा-अनिष्ठा का भाव भी राजनीतिक दृष्टिकोण से तय होने लगा है।

इन तमाम परिस्थितियों के चलते ऐसा माना जाता है कि जमाना खराब हो चला है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि हम जमाने से हैं या जमाना हमसे है! दरअसल अंतर केवल अपने-अपने दृष्टिकोण का है। दुर्भाग्य से आजकल दृष्टिकोण भी राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर तय होने लगा है। अब यदि कोई कहे कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं या कि हम पतन के गर्त में जा रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा यह अर्थ निकाल लिया जाता है कि वह इस राजनीतिक दल या गठबंधन का समर्थक है। अब ऐसी स्थिति में असल सवाल यह उठता है कि वास्तव में वैश्विक परिदृश्य में हमारी अपनी स्थिति क्या है ? यह अनुत्तरित सवाल आदमी को तोड़ कर रख देता है। हमें ही पता नहीं होता कि हम कहां हैं ?

दरअसल हमारे यहां राजनीति में ही राजनीति नहीं होतीअपितु धर्म और सामाजिक संरचना में भी राजनीति की घुसपैठ हो चली है। यही कारण है कि सकारात्मक से सकारात्मक परिस्थितियों को भी लगातार नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। राजनीति में अब नीति और सिद्धांतों को लेकर मतभिन्नता का स्थान काफी हद तक व्यक्तिगत विद्वेष के रूप में दिखाई देता है। सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष का अस्तित्व नहीं सुहाता और प्रतिपक्ष को सत्तापक्ष का अस्तित्व नहीं सुहाता, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। जनमानस के चिंतन को सही दिशा देने की दिशा में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। लेकिन मीडिया को भी राजनीतिक धुरंधरो ने तो अलग-अलग खेमे में बांट दिया है।

इन तमाम परिस्थितियों का परिणाम यह हो रहा है किव्यक्ति की सोच आजकल अपने और अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है। बीते जमाने में संपन्न वर्ग विपन्न वर्ग की हर स्तर पर सहायता करने को तत्पर रहा करता था। लेकिन आजकल के दौर में संपन्न वर्ग अपनी संपन्नता बढ़ाने की दिशा में ही मशगूल है। एक प्रकार से अमीरों की बढ़ती अमीरी गरीबों की बढ़ती गरीबी का कारण बन रही है। दरअसल ऐसी परिस्थिति के नकारात्मक परिणाम के संदर्भ में गंभीर चिंतन किया जाने की नितांत आवश्यकता है। इतिहास की घटनाओं से भी सबक सीखा जाना चाहिए। समाज में बढ़ते निरंतर अपराधिक प्रकरण इस स्थिति के अंदेशे की ओर साफ तौर पर इंगित करते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

'बाल की खाल' उतारने का शौक

व्यंग्य

संजय तेलंग

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बरसों अखबार से जुड़ा रहा हूं, इसलिए ख़बरों को पढ़ते समय बेहद संजीदा रहता हूं। खबर क्यों लिखी या लिखवाई या प्रकाशित की गई, उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, यह समझते देर नहीं लगती। लोग मेरी इस आदत को 'बाल की खाल उतारना' कहते हैं। जब ऐसी ही बाल की खाल उतारकर मैं अपने साथियों को बताता हूं, तो उनका नैराश्य भाव से जवाब होता है 'भाई यह दुनिया है, ऐसे ही चलती है और चलती रहेगी। आपके कुछ कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। अपना काम करो और मस्त रहो।'

वैसे इस बारे में मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूं, अखबारों में बरसों काम करने के अनुभव से ही तो विधा हासिल हो सकी है। मैं अखबार में ख़बरें सिर्फ सूचनाओं को जानने के लिए कभी नहीं पढ़ता, बल्कि खबरों के पीछे की खबर जानना मेरी जिज्ञासा रहती है। अब मेरी इस आदत को कोई भी नाम दे दिया जाए, मेरी बला से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, मुद्दे की बात पर आता हूं। अपनी बात उदाहरणों के साथ रखूंगा। आपने अखबारों में एक खबर देखी होगी कि 'पुलिस ने किसी शातिर बदमाश को धरदबोचा। बदमाश पर अनेक मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।' खबर सामान्य है लेकिन खबर में असामान्य बात यह है कि जब पुलिस ने बदमाश को घेरा तो उसने भागने का प्रयास किया। भागमभाग में अपराधी के हाथ-पैर टूट गए। क्या यह बात गले उतर सकती है कि एक शातिर बदमाश, जिसने बड़े-बड़े तुर्रम खां के छक्के छुडाए हों, थोड़ी सी भागदौड़ में गिर कर हाथ-पैर तुड़वा बैठे। मेरे गले तो यह बात नहीं उतरी। इस तरह की ख़बरें मैं बरसों से अखबारों में देख रहा हूं, जिनकी भाषा और खबर का गठन बिलकुल समान रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस गहराई में न जाते हुए मैं तो यही कहूंगा-यह बाल की खाल उतारना नहीं, बल्कि खबर की तह टटोलना है!

वाह पुलिया! इसी तरह एक अन्य खबर और देखिए। अखबारों के अपराध समाचार वाले पन्ने पर नियमित प्रकाशित होने वाली इस खबर को आपने भी पढ़ा या देखा होगा। 'पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते बदमाशों को पुलिया के नीचे से पकड़ा।' इस तरह की सैकड़ों खबरें मैं अख़बारों में देख चुका हूं। लेकिन, आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि बदमाश अपराध की योजना पुलिया के नीचे बैठकर ही क्यों बनाते हैं?

पुलिया के नीचे ऐसा क्या है? क्या वहां अपराध की योजना बनाने से कार्य सिद्ध होने का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है? या फिर वह पुलिया नहीं बोधि वृक्ष है, जहां बदमाशों को ख़ास ज्ञान प्राप्त हो जाता हो। मैं यह भी नहीं समझ पाया कि बार-बार एक ही स्थान से पकड़े जाने के बावजूद बदमाश फिर पुलिया के नीचे योजना बनाने क्यों पहुंच जाते हैं। लगता है वे अखबार भी नहीं पढ़ते, क्योंकि पढ़ते होते तो उन्हें मालूम होता कि पुलिया के नीचे पुलिस के पहुंच जाने का जोखिम है! अब यह आप पाठकों पर छोड़ता हूं कि सोचें ऐसा क्यों होता है?

सूंघो मीटर चलते-चलते एक और बात। इस बार होली पर एक नया शब्द जानने को मिल गया। शराब पीकर हुडदंग मचाने और मदिरा पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस एक उपकरण का उपयोग करती है। उपकरण का अंग्रेजी नाम थोड़ा कठिन है। छोटे पुलिसकर्मियों की जुबान पर भी अक्सर नहीं चढ़ पाता। नाम है 'ब्रीथ एनॉलाइजर'। पुलिसकर्मी इसमें फूंकने को कहते हैं और पता लगा लेते हैं कि किस-किस बंदे ने इत्र! लगाया है। वैसे उपकरण का मीटर भी बता देता है कि कितना अल्कोहल कंज्यूम किया गया है। 'ब्रीथ एनॉलाइजर' का हिन्दी में बेहतर शब्द हमारे एक साथी ने बताया 'सूंघो मीटर।' हिंदी का यह शब्द बोलने और समझने दोनों में आसान होगा। चाहें तो संबंधित आजमा कर देख सकते हैं।

निपटान का महीना मार्च

वक्रोक्ति

डॉ. अतुल चतुर्वेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मार्च का महीना बजट निपटाऊ महीना है। जिसे देखो बजट निपटाने में लग रहा है। उधर कुछ लोग देश निपटाने में लग रहे हैं तो कुछ अपने वैवाहिक संबंधों में आई खरपतवार और फफूंदों को निपटाने में लग रहे हैं। क्या करें साहब सबका अपना अपना निपटान अभियान है। इजराइल दुनिया में अनुपम उदाहरण पेश कर मासूम शरणार्थियों और अबोध बच्चों को निपटने में लग रहा है। रूस यूक्रेन को निपटा रहा है और इसके प्रति प्रतिबद्ध है । न्यायाधीशगण न्यायपालिका को निपटा कर अनूठा प्रतिमान स्थापित करने की सोच रहे हैं । कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई निपटान महोत्सव पूरे विश्व में चल रहा हो । जिसे जब जहाँ मौक़ा मिलता है निपटाने से नहीं चूकता अपने से कमज़ोर को। लेकिन प्रश्न यह है कि निपट कौन रहा है मजलूम, मासूम और निरीह जन क्योंकि समर्थ तो कोई गली बचाव की तलाश ही लेता है ।

ठीक इसी तरह निपटान माह मार्च की तरह सरकारी विभागों में या कंपनियों में क्लोजिंग का भूत आ कर ताल ठोंकता खड़ा हो जाता है। है दम, तो आओ निपटाओ मुझे। सरकारी विभाग साल भर बजट का रोना रोते रहते हैं। कई जरूरी काम बजट के अभाव में स्थगित रहते हैं। स्टाफ टूटी कुर्सियों पर काम करता रहता है, शौचालय सफाई के बजट के अभाव में बदबू का अखिल भारतीय प्रसार करते रहते हैं, महिला कार्मिक अलग शौचालय की गुहार लगाती रहती थक जाती हैं लेकिन सभी परिवेदनाएं बजट अभाव में दम तोड़ती रहती हैं और बजट है कि गूलर का फूल सा हो जाता है ।क्या करें साहब बजट नहीं है नहीं तो ऑफिस को फाइव स्टार बनवा देते। लेखाधिकारी का चुनावी वादों सा बयान भरोसे के तिरपाल सा ढक जाता है सभी कष्टों के ऊपर।

लेकिन कहते हैं न ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है अचानक मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट आ टपकता है कार्यालय में। विभागों की तन्द्रा टूटती है उन्हें इलहाम होता है कि अरे अभी तो इतना पैसा पड़ा है फंड में। इस्तेमाल करो नहीं तो लैप्स हो जाएगा और आनन फानन में इमदाद का टोकरा ऑफ़िसों में किसी नये नवेले बच्चे की किलकारी सा शोर मचाने लगता है। बजट आ गया,बजट आ गया की हर्षोल्लास से तरंगित ऊर्जा पूरे वातावरण में खुशी का संचार कर देती है। कार्यालय की समूची ऊर्जा और पूरी कायनात बजट को निपटाने के महाभियान में लग जाती है । फ़ुर्सत पाते ही कर्मचारियों का परिचर्चा विषय एक ही होता है - सुना है कि बजट आ गया है । मानों बजट नहीं सेंटा क्लॉज आ गया हो। कोई स्टेशनरी की मांग लेकर आ रहा है तो कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग की तो कोई लंबित पड़े टी ए बिल की। हर प्रकार से बजट के जल्दी से जल्दी उपयोग की जुगत ढूंढी जाने लगती है। ऐसे में कार्यालय में कुछ कर्मचारी होते हैं जो वैसे भले ही नकारा सामान से हों लेकिन बजट निपटान में उनको महारत हासिल होती है

वो पूरे विभाग को निपटाते रहते हैं बजट तो चीज़ ही क्या है । उनकी विशेषज्ञ सेवाओं की अधिकारी को तुरंत आवश्यकता पड़ती है और वे कहीं से भी तीन बिलों का टेंडर सहित जुगाड़ प्रस्तुत कर देते हैं । कहाँ कौन सा माल सड़ा मिलेगा और कौन विक्रेता बिन माल सप्लाई के बिल दे देगा तुरंत उन्हें इसका इतिहास भूगोल रटवाँ याद होता है । उनका अक्खा जीवन ही इस कला की सिद्धहस्तता में बीता। कंपनियों में क्लोजिंग के भूत कि वजह से समस्त कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त कर दी जाती हैं। क्लोजिंग का आतंक इतना होता है कि घटिया माल भी खप जाता है और काम के घंटों की थकान छू मंतर हो जाती है। युद्ध स्तर पर सामग्री तैयार की जा रही होती है और ऐरे गैरे नत्थू खैरे भी दूरदर्शन और आकाशवाणी में कविता या व्यंग्य पाठ की फोटो सहित पोस्ट डाल कृत कृत्य महसूस करते हैं। घूरे के भी दिन चेत जाते हैं जिनको पद्य और गद्य का ठीक अंतर भी पता नहीं वो विश्व कविता दिवस पर सम्मानित हो जाते हैं । सब बजट की महिमा है और निपटान का प्रेशर। निपटान का प्रेशर इंसान से क्या नहीं करवाता। मार्च का माह होता ही ऐसा ज़ालिम है। कभी इनकम टैक्स की मार तो कभी बजट की दहाड़ चैन से सोने ही नहीं देती और ऐसे में कहीं सेंसैक्स गिर जाये तो व्यक्ति का बी पी भी गिर जाता है। ऐसे विपरीत हालातों में कमरे में नकदी मिलने की खबरें कुछ उम्मीद जगाती हैं। निराशा के बादल छंटते हैं कि धरती अभी वीरों से खाली नहीं है। सब अपनी अपनी तरह से निपटा रहे हैं कोई रिश्तों की आड़ में तो कोई सुविधाओं की बाढ़ में। हर नए बजट की मार से ग़रीब की आह कम नहीं अलबत्ता तेज होती है लेकिन करतल ध्वनियों के शोर में उसकी सुनने वाला कौन है क्योंकि एक दूसरे को निपटाने से फुर्सत मिले तब तो।

चिंतनीय है न्यायपालिका की गिरती साख

मुद्दा

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर और न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य के टीले में दबे सिंहासन पर अनजाने में बैठे ग्वाल बच्चे की न्याय क्षमता की कहानियां पढ़कर जो बच्चे से बूढ़े हो गए , वे इन दिनों न्यायपालिका पर उठते सवालों को लेकर निश्चित रूप से बहुत आहत होंगे । कानूनी पेशे से जुड़े काले चोगो में दिखते संभ्रांतो के लिए इंग्लैंड के तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस लॉर्ड हेवार्ट की यह ना भूलने वाली टिप्पणी भी बहुत मायने रखती है 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि न्याय किया गया है।' आज की तारीख में एक आम नागरिक में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने तथा महंगे अधिवक्ताओं की फीस चुकाने का सामर्थ्य ही कहां बची है ।

सामान्यतः भारत की न्यायपालिका की साख कुछ विवादास्पद फैसलों के बावजूद कायम है । नागरिक, राजनीतिक अधिकार, व्यक्तिगत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शासन की शक्तियों का वितरण और संघवाद की प्रकृति से जुड़े कई मुद्दों पर न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले सुर्खियां में एवं चर्चित रहे है । इन फैसलों को स्वस्थ लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मानक माना गया । उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले ऐसे भी थे जिन्हें वर्षों बाद उच्चतम न्यायालय की बड़ी बेंच ने पलट दिए । बावजूद इसके न्यायपालिका की निष्पक्षता , साख पर थोड़ी बहुत हलचल से अधिक कुछ प्रभाव नहीं हुआ । इन फैसलों का सबसे महत्पूर्ण पक्ष यह है कि उस समय तक न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच कोई बड़ी टकराहट नहीं थी । उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के जजों की नियुक्ति में सीधा सरकारी हस्तक्षेप था । लेकिन न्यायपालिका के निर्णयों को प्रभावित करने वाला सबसे विवादास्पद निर्णय तत्कालीन केंद्रीय सरकार का उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ जजों की वरीयता को दर किनार कर अन्य कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायधीश नियुक्त करना था । राज्य सभा के एक सांसद रहे राजनेता को उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में नियुक्ति एवं रिटायरमेंट के बाद पुनः राज्य सभा सदस्य बनाने के बाद न्यायपालिका के राजनीतिकरण की शुरुआत हो चुकी थी । बाद की सरकारों ने भी ऐसी नियुक्तियों का लाभ लेने में कोई झिझक महसूस नहीं की । 'सरकार एवं न्यायपालिका की सोच एक हो' जैसे विषय भी लंबे समय तक चर्चा में रहे । 1993 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय से न्यायधीशों की नियुक्ति में मुख्य एवं अन्य वरिष्ठ न्यायधीश की राय धीरे धीरे न्यायधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम का एकमेव अधिकार बन गया । न्यायपालिका के इस एकाधिकार के बाद सन 2014 में संसद के दोनों सदनों ने जजों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) बनाने के लिए संविधान का 90 वा संशोधन पारित किया। 16 राज्य विधान सभाओं द्वारा पुष्टि एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। जबकि कॉलेजियम की भी संवैधानिक मान्यता नहीं है । तत्कालीन कानून मंत्री के कॉलेजियम सिस्टम को 'एलियन' करार देने के बाद यह सरकार एवं न्यायपालिका के बीच अघोषित युद्ध सा बन गया है। हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों, अधिकारों की सूक्ष्म व्याख्या के बावजूद इस तरह सीमाओं का किसी भी संस्था द्वारा उल्लंघन लोकतंत्र की मर्यादा का हनन है । उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को कई ऐसे विशेषाधिकार है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भी नहीं ।

इन सब के बावजूद आम नागरिक मौन ही रहा है , लेकिन जस्टिस वर्मा के निवास परिसर के बाहरी कमरे में पाए गए अध जले नोटों की घटना एवं अपनाई जा रही जांच प्रक्रिया से न्यायपालिका की साख को जो ठेस पहुंची है उसे वापस पाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की ही है । देखना होगा न्यायपालिका की आंख पर से पट्टी हट जाने के बाद उसे कितना सच नजर आता है ?

ऑनलाइन दुनिया में खोते रिश्ते और संवेदनाएँ

समाज

सुप्रिया सत्यार्थी

आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। तकनीक ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसने हमें वास्तविकता से कितना दूर कर दिया है, यह सोचने वाली बात है। आजकल, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, उसे कैमरे में कैद करने की होड़ सी मची रहती है। चाहे वह कोई खूबसूरत दृश्य हो, कोई खास लम्हा हो या फिर कोई भावनात्मक क्षण, हम उसे पूरी तरह महसूस करने से पहले ही अपने मोबाइल फोन या कैमरे में संजोने में लग जाते हैं। यह सही है या गलत, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कैमरे में कैद की जाने वाली तस्वीरें सिर्फ दृश्य को सहेज पाती हैं, अनुभव कोनहीं।

कभी-कभी लगता है कि यह दुनिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। रिश्ते,भावनाएँ, संवाद-सबकुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिमट कर रह गया है। हम ऑनलाइन लोगों से जुड़ने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे आसपास जो लोग वास्तव में हमारे साथ हैं, उनकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगे हैं। एक समय था जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर बातें किया करते थे, हँसी-ठिठोली होती थी, किस्से-कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती थीं। लेकिन अब, सुबह उठने से लेकर रात तक हमारी आँखें मोबाइल स्क्रीन पर ही टिकी रहती हैं।

बदलते दौर के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई है। पहले जहाँ परिवार के बड़े-बुजुर्ग बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, वहाँ अब मोबाइल और टैबलेट ने उनकी जगह ले ली है। दादा-दादी और नाना-नानी की कहानियाँ, जिनमें जीवन के गहरे अनुभव और नैतिक शिक्षाएँ हुआ करती थीं, अब मोबाइल एप्लिकेशन और वीडियो स्टोरीज़ में बदल गई हैं। बच्चे अब पबजी, टेंपल रन, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम्स में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें असली दुनिया की कहानियों, परिवार की गर्मजोशी और इंसानी जज़्बातों की पहचान ही नहीं रही।

बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। आज के युवा भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हेंअपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल कम और ऑनलाइन स्टेटस, लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। किसी समारोह में जाने के बाद हमें यह कम याद रहता है कि हमने वहाँ क्या महसूस किया, किन लोगों से मिले, किससे क्या बात की, लेकिन हमें यह जरूर याद रहता है कि हमने कितनी अच्छी तस्वीरें क्लिक कीं और कितने लाइक्स मिले।

यह सच में चिंताजनक है कि धीरे-धीरे हम संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं। अगर कोई पास बैठा हो और उदास हो, तो हम उसे देखने के बजाय यह सोचते हैं कि उसकी उदासी के बारे में कोई इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकता है या नहीं।असल में, ऑनलाइन दुनिया ने हमें इतना आत्मकेंद्रित बना दिया है कि हम अपने आसपास के लोगों के दर्द, उनकी खुशियों, उनकी जरूरतों से बेखबर होते जा रहे हैं।

ऑफलाइन रिश्तों की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। एक समय था जब रिश्ते भावनाओं के धागे से जुड़े होते थे, अब वे इंटरनेट की स्पीड और नेटवर्क कनेक्शन पर निर्भर हो गए हैं। पहले दोस्त एक-दूसरे से मिलते थे, घंटों बातें करते थे, एक-दूसरे की परेशानियों में साथ खड़े रहते थे। अब व्हाट्सएप पर 'तू ठीक तो है?' लिखकर भेज देना ही दोस्ती निभाने का सबूत बन गया है। पहले लोग अपने दुख-दर्द, अपनी खुशियाँ अपनों के साथ बाँटते थे, अब वे इन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके ऑनलाइन मित्र उनकी भावनाओं को समझेंगे।

इस डिजिटल युग में हम धीरे-धीरे अपने आसपास के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हम बस 'ऑनलाइन उपलब्ध? हैं, लेकिन वास्तविकता में 'इमोशनली अनअवेलेबल' होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के आभासी रिश्तों ने हमारे असली रिश्तों की गर्मजोशी को धीरे-धीरे खत्म कर दिया है। पहले जब कोई रिश्तेदार घर आता था, तो हम उसे सम्मानपूर्वक बैठाते थे, उनसे बातें करते थे। आज के दौर में कोई आता है, तो सबसे पहले उसका वाई-फाई पासवर्ड पूछा जाता है।

इस ऑनलाइन दुनिया में हमें यह भी समझना होगा कि हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस डिजिटल भँवर में धकेल रहे हैं। बचपन में जो प्रेम, अपनापन और साथ की अहमियत हम महसूस करते थे, वह अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। यह देखकर डर लगता है कि आने वाली पीढ़ी संवेदनशीलता के बिना ही बड़ी हो रही है। रिश्ते निभाने के लिए अब समय और भावनाओं की जगह सिर्फ टेक्स्ट और इमोजी रह गए हैं।

समय रहते अगर हमने खुद को नहीं बदला, तो आने वाले समय में इंसान संवेदनाओं से पूरी तरह दूर हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक माध्यम है, जीवन नहीं। असली खुशी तस्वीरों में नहीं, बल्कि उन लम्हों को महसूस करने में है। किसी जगह पर जाकर फोटो खींचने से ज्यादा जरूरी है कि उस जगह की हवा को महसूस किया जाए।

रिश्ते ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन संवेदनाएँ ऑनलाइन नहीं हो सकतीं। संवेदनाओं को महसूस करने के लिए, उन्हें संजोने के लिए और उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए असली दुनिया में रहना जरूरी है। इसलिए, कभी-कभी फोन को थोड़ा दूर रखकर, अपनों के साथ समय बिताना सीखें। वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारी यादें सिर्फ फोन की गैलरी में तो होंगी, लेकिन हमारे दिल में नहीं।

बेरोजगार संरक्षण अधिनियम कानून आवश्यक

सामयिक

डॉ.संजीव कुमार

सहायक प्राध्यापक, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई

बुधवार को एक बार फिर सरकारी नौकरी का एक बड़ा परीक्षा होते होते टल गया। इस बार रद्द होने वाले परीक्षा में लोको पायलट की बारी थी। गौरतलब है कि यह परीक्षा लगभग दो साल से अब तक उलझी हुई थी, इस परीक्षा का प्रथम सत्र यानी प्री परीक्षा होने के पश्चात उन्नीस मार्च को मुख्य परीक्षा होनी थी, पर अंत में आखिरी दिन यह परीक्षा टाल दी गई और फिर से लाखों बेरोजगार नवयुवक अपना बस्ता समेट कर अपने घर लौट आए है।अब ये घर बैठकर प्रतीक्षा करेंगे कि सरकार इस परीक्षा को पुनः कराने का कब आदेश पारित करेगी और वे फिर से परीक्षा की तैयारी में जुटकर अपने सपने कों जिन्दा रखने का प्रयास करेंगे।

शीतकालीन लोकसभा सत्र में विपक्ष का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 70 से ज्यादा परीक्षाएं या तो रद्द हुई है या फिर पर्चा लिक हुआ है। इस 70 में एसएससी, पीसीएस,नीट,जे ई ई,यूपी पुलिस,बिहार पुलिस जैसी बड़ी-बड़ी भर्तियां शामिल है। आज जिस प्रकार से शिक्षित नवयुवकों का भविष्य सरकार की गलत नीतियों और योजनाओं की वजह से अधर मैं लटका हुआ है युवाओं के भविष्य से लगातार सरकार खेल-खेल रही है ऐसे में अब आवश्यक है कि बेरोजगार नवयुवकों के लिए सरकार उनकी बेरोजगारी की सुरक्षा का अधिनियम पारित कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें।

हम जानते है कि आज देश में एक छोटी भर्ती से लेकर बड़ी भर्ती तक पर बेरोजगार युवकों की नजर टिकी हुई रहती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार एक तो बहुत विवश होने के बाद ही कुछ वैकेंसी लेकर आती है। जब सरकार को लगता है कि अब बिल्कुल ही काम नहीं हो पाएगा तब वह वैकेंसी निकलती है। फिर इस वैकेंसी को भरने के लिए बेरोजगार युवकों को अपनी श्रेणी के अनुसार उसका शुल्क भी अदा करना पड़ता है। और इधर आप देखेंगे तो लगातार सरकारी योजनाओं द्वारा निकलने वाली भर्तियों के शुल्क बढ़ते जा रहे है इन आवेदनों कि फीस पांच सौ से कम देखने को नहीं मिलेंगे। जब एक युवक इस आवेदन को भरता है तो उसके साथ आरम्भ होती है उसकी वह युद्ध जो न जाने कितने आवेदन करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाता । वह आवेदन करने के बाद संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तक खरीदता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता है फिर गांव से दूर शहर में जाकर किराए पर मकान लेता है और परीक्षा की तैयारी में जीजान से जुट जाता है। फॉर्म निकलते समय उसे यह बताया जाता है कि यह भर्ती यथा शीघ्र साल भर के अंदर पूरी हो जाएगी और फिर इसी हिसाब से यह नवयुवक अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। इनमे बहुत से नवयुवक वें भी होते हैं जो डिग्रियां हासिल करने के बाद कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, कुछ अपना छोटा-मोटा व्यवसाय खड़ा कर रहे होते हैं, कुछ परिवार के सहयोग के लिए बड़े शहरों में जाकर के

छोटा-मोटा काम करते हैं। पर जैसे ही उनके मन मुताबिक सरकार वैकेंसी निकालती है वें सब कुछ छोड़ करके तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं।

कभी-कभी कुछ वैकेंसी की परीक्षाएं तो चार-चार पांच-पांच साल तक घसीट जाती है ऐसे में उनके मित्र, पड़ोसी,रिश्तेदार लगातार उनके रोजगार के विषय में पूछते रहते हैं जिसका वें जवाब दे दे कर थक चुके होते हैं। लड़के अपने परिवार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए घर से पैसे मांग मांग करके थक चुके होते हैं पर लालच बस की अब चार महीने में उनका जीवन सेटल हो जाएगा वें घर से पैसे मांगते रहते हैं। परिवार के लोग भी पैसे दे दे कर परेशान हो चुके होते हैं परंतु नहीं करने की उनमे में भी हिम्मत नहीं होती और वह अपनी जमीन बेचकर अपने जेवर बेचकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पैसे देते रहते हैं, और ऐसे में जब इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवकों को लगातार परीक्षा रद्द होने तिथि बदलने की सूचना मिलती है तो यह निराश होने लगते हैं और अवसाद में चले जाते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं कुछ तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। पर सरकार को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है और जब ऐसे में यह युवक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर आंसू गोले छोड़ जाते हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है। आखिरी इन युवाओं का कसूर क्या होता है? क्या अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी प्रतियोगिता तैयारी करने के बाद इनका अधिकार नहीं है कि सरकार ठीक-ठाक इन्हें जीवन गुजारने के लिए नौकरी दे सके।

इसलिए इन करोड़ों युवाओं के भविष्य कों सुरक्षित रखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन बेरोजगार युवकों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए तथा परीक्षा देने के लिए सरकार को ब्यापक प्रबंध करना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सभी शुल्क हटा देनी चाहिए और यदि समय पर परीक्षा ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में इनके पुनः परीक्षा कराने की पूरी व्यवस्था निशुल्क सरकार के द्वारा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक उम्र और सीमा के बाद इन्हें बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करना चाहिए। तभी हम अपने युवाओं के हौसलों को बचा पाएंगे और उन्हें अवसाद, आत्महत्या, निराशा के अंधकारमय जीवन से बाहर निकाल पाएंगे।

रविन्द्र भवन में दो दिवसीय जल महोत्सव

- 'वाटर फॉर आल, आल फॉर वाटर फेस्टिवल' का मंत्री परमार ने किया उद्घाटन

भोपाल। 'वाटर फॉर आल, आल फॉर वाटर फेस्टिवल' का उद्घाटन माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने 28 मार्च को किया, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की निर्देशक सरिता बाला ओम प्रजापति, पूर्व आईपीएस अनुराधा शंकर सिंह, वेल्थहंगरहिल्फे के कंट्री डायरेक्टर राकेश कटल, जलपुरुष रंजन पंडा, यूनिसेफ से वॉश ऑफिसर नरेंद्र सिंह चौहान, वाटर एड से डॉ. विश्वनाथ सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मयंक चतुर्वेदी, डॉ. योगेश कुमार और संजय सिंह अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन वेल्थुंगरहिल्फ़ और विवा कॉन अगुआ ने अपने सहयोगियों परमार्थ समाज सेवा संस्थान और समर्थन - विकास केंद्र के सहयोग से किया। वेल्थुंगरहिल्फ़ इंडिया के कंट्री डायरेक्टर राकेश कटल ने कहा कि वाटर फॉर ऑल, ऑल फॉर वॉटर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य ग्रामीण लोगों, नीति निर्माताओं, दानदाताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, कलाकारों और जागरूक नागरिकों के बीच एक पुल का निर्माण करना है ताकि सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें। यह फेस्टिवल हमारे अद्वितीय यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर बिहेवियर चेंज दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा, जो कमजोर समुदायों को सक्रिय करने, प्रेरित करने, जोड़ने और बदलने के लिए खेल, कला और संगीत जैसे मनोरंजक और मजेदार उपकरणों का उपयोग करता है। 29 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रवींद्र भवन में ललित कला में प्रदर्शनी लगी रहेगी जो सभी के लिए खुली रहेगी और कविता और कहानी की प्रस्तुति दी जायेगी, व्यवहार परिवर्तन के लिए फण्डरेजिंग पर राउंड टेबल और लाइव आर्ट जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। आर्ट रीच द्वारा आर्ट स्पेस में बच्चे चित्र और पेंटिंग बना सकते हैं।

श्री शिलनाथ धुनी संस्थान पर धूमधाम से मना समाधि महापर्व

- तीन दिवसीय महोत्सव का समापन

देवास। श्री शिलनाथ धुनी संस्थान पर तीन दिवसीय समाधि महापर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री शिलनाथ धुनी संस्थान के प्रबंधक दिलीप शर्मा ने बताया कि सदगुरु श्री योगेंद्र शिलनाथ महाराज का समाधि महापर्व उत्सव दिनांक 26 से 28 मार्च तक तीन दिवसीय उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत बुधवार को शाम 7 बजे सदगुरु श्री शिलनाथ महाराज की शोभायात्रा चल समारोह रथ में विराजित होकर नगर भ्रमण किया। जिसमें सैकड़ो भक्तों ने हिस्सा लिया। 27 मार्च गुरुवार को प्रातः 6 बजे सदुरु गुरुदेव की प्रतिमा का अभिषेक पूजन किया गया। प्रातः 9 बजे आरती की गई उसके पश्चात शाम को महाआरती की गई। 28 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ जो देर शाम तक चलता रहा। उक्त समारोह में ट्रस्ट के भगवान सिंह चावड़ा, महेंद्र पडियार, राजेंद्र महंत, पं. भूपेंद्र तिवारी, शरद पाचुनकर, मनोज राजनी, दिनेश बैरागी, नरेंद्र यादव, राजेश राठौर, परमानंद द्विवेदी, रमेश व्यास, सूरज सिंह गौड, निलेश वर्मा, रोशन रायकवार सहित बडी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। तीन दिन महोत्सव में सेवा समिति के मंथन पडियार, प्रमोद चौहान, चेतन पवार, उमेश चौहान, दिव्यांशु, जयराव, पं. उपाध्याय जयसिंह, जीवन सिंह सोनगरा का विशेष सहयोग रहा। भक्तजनों का आभार ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत भल्ला, भगवान सिंह चावड़ा, राजेंद्र महंत एवं महेंद्र पडियार माना।

स्त्री रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन महिला स्वास्थ्य के प्रति एक सार्थक पहल : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में स्त्री रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन महिला स्वास्थ्य के प्रति एक सार्थक पहल है। सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जटिल समस्याओं पर मंथन होगा और इससे निकलने वाले परिणाम मातृ मृत्यु दर व नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायक होंगे। एसोसियेशन आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलाजी सोसायटी के तत्वाधान में देश, प्रदेश के स्त्री रोग विशेषज्ञों के महासम्मेलन में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की गर्भवस्था संबंधी जटिलताओं, प्रसव की नई तकनीकों, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रभावी उपायों पर सम्मेलन में विचार विमर्श होगा और उसको सार्थक परिणाम सामने आयेंगे। उन्होंने कहा कि रीवा में चार दिनों तक आयोजित हो रहे इस आयोजन से यह परिलक्षित होता है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये चिंतित है। गांव-गांव तक मिशन मोड में काम करते हुए महिलाओ के स्वास्थ्य के प्रति सार्थक पहल करनी होगी। जनप्रतिनिधियों एवं समाज को भी आगे आना होगा तभी प्रदेश में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन कराकर उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच आवश्यक है। स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक माह की 9 एवं 25 तारीख को स्त्री विशेषज्ञ अनिवार्यतः उपस्थित रहकर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच करें साथ ही मैदानी स्वास्थ्य आमला पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से इसमें सहयोग करते हुए गर्भवती महिलाओं के परिजनों को भी जागरूक करें। सभी के समन्वित प्रयासों से ही प्रदेश में मातृ मृत्यु पर व शिशु मृत्यु दर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की भर्ती जारी है। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी डाक्टर्स कालोनी बनाई जायेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहे चिकित्सकों को असुविधा न हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्मारिका का विमोचन किया।

मध्यप्रदेश को मिली बड़ी सौगात

290 करोड़ की लागत से प्रदेश में बनेंगे 8 वूमेन वर्किंग होस्टल : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर

- मंत्री सावित्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जताया आभार

धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राज्य के आठ जिलों में वूमेन वर्किंग हॉस्टल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 290.25 करोड़ रुपये की लागत से इन हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी एक वूमेन वर्किंग हॉस्टल की स्थापना होगी, जिसकी लागत 76.46 करोड़ रुपये है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है और यह प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ नीयत को दर्शाता है कि वह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इन वूमेन वर्किंग हॉस्टल बनने से महिलाओं को उनके कार्यस्थलों के नजदीक ही सुरक्षित आवास की समुचित व्यवस्था होगी इससे महिलाओ के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । खासकर उन महिलाओं के लिए, जो शहरों में या औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में आती हैं और घर से दूर रहती हैं। ऐसे कार्यस्थल पर रहने वाली महिलाओं को न केवल सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बल्कि एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां उन्हें काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सके। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर ने इस पहल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि

इस योजना से राज्य की महिलाओं के लिए एक नई दिशा का निर्धारण होगा और यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमती ठाकुर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए लगातार सकारात्मक योजनाओं पर काम कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को हमेशा उनके हक और अधिकारों का सम्मान मिला है। मध्य प्रदेश के आठ जिलों में बनने वाले वूमेन वर्किंग हॉस्टल में महिलाओं को रहने, खाने और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह हॉस्टल महिला कामकाजी आबादी के लिए एक सशक्त कदम साबित होंगे और उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को बढ़ावा देंगे। खासकर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले हॉस्टल से वहां काम करने वाली महिलाओं को एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण मिलेगा, जो उनके जीवन को और बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर सकारात्मक कदम उठा रही है। इस पहल के साथ, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें और अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, तो समाज और राष्ट्र का भी विकास होता है। यही कारण है कि उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और इसके लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिनमें वूमेन वर्किंग हॉस्टल का निर्माण भी एक अहम पहल है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री की नीतियों और योजनाओं ने राज्य में महिलाओं के लिए कई अवसर प्रदान किए हैं। वूमेन वर्किंग हॉस्टल का निर्माण भी मुख्यमंत्री की दृष्टि को प्रदर्शित करता है कि राज्य में महिलाओं को उनके कार्यों के लिए एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना के माध्यम से राज्य में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। इसके अलावा, महिला कार्यशक्ति को और अधिक सशक्त करने के लिए उनके कार्यस्थलों के पास हॉस्टल्स का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह महिलाओं की भलाई और उनके उत्थान के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यह पहल केवल शुरुआत है, और इसके अलावा भी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए विकास के नए अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और महिला सुरक्षा प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की योजनाएं शामिल हैं। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं, कौशल विकास केंद्र, और उद्यमिता कार्यक्रम भी भाजपा सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और सशक्त बनने का मौका मिल सके। जानकारी मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।

उधार ली राशि के बदले सूदखोरों ने जमीन की करवाई रजिस्ट्री,पीड़िता भटक रही सुनवाई के लिए

देवास/मोहन वर्मा। रेखाबाई पति कैलाश मालवीय निवासी ग्राम जिनवानी तह. सतवास जिला देवास रहवासी ने पत्रकारों के समक्ष अपना दुःख रखते हुए बताया मेरे द्वारा वर्ष 2019 में ग्राम जिनवानी के ही निवासी रेखा पति संतोष मेहर, सोनम पति पवन मेहर, पवन पिता बद्रीप्रसाद, और संतोष मेहर पिता बद्रीप्रसाद से मेरे ससुर रणजीतसिंह के उपचार हेतु, घरेलु कार्यो एवं कृषि के कार्य में आवश्यकता होने के कारण 16 लाख रूपये 2 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार लिये गये थे। हमारे क्षेत्र में एक परम्परा है कि जब किसी को राशि की आवश्यकता होती है तो वह अपनी जमीन की रजिस्ट्री उधार देने वाले व्यक्ति के नाम करवाता है और फिर जब वह उक्त राशि वापस लौटाता है तो सामने वाला व्यक्ति राशि प्राप्त होने के बाद फिर से जमीन की रजिस्ट्री जमीन मालिक के नाम सम्पादित करवा देता है। इस परम्परा के तहत हमारे ग्राम व क्षेत्र के लोगों ने इस प्रकार से जरूरत पडने पर लेनदेन किया है व जमीन की लिखापढी व रजिस्ट्री की है। मुझ प्रार्थी रेखाबाई ने भी इसी परम्परा के तहत उक्त लोगों से 16 लाख रूपयें की राशि ली थी, किन्तु जब राशि का इंतजाम होने पर मै इन लोगों को राशि वापस लौटाने गई तो वह अपनी बात से मुकर गये। मेरे द्वारा 16 लाख के बदले 20 लाख रूपयें की राशि देने का निवेदन भी इन लोगों से किया गया था, लेकिन जमीन का भाव अधिक होने की वजह से इन लोगों की नियत में लालच उत्पन्न हो गया और वह जालसाजी कर मेरी पूरी 6 एकड जमीन हडप कर गये है। हमारे क्षेत्र में 8 लाख रूपयें प्रति एकड की शासकीय गाईड लाईन है और मेरे द्वारा मेरी 6 एकड जमीन पर मात्र 16 लाख रूपयें उधार लिये गये थे, जिसके बदले उक्त आरोपियों ने मेरी पूरी 6 एकड जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली है मुझ प्रार्थियॉ को गाईड लाईन के हिसाब से भी राशि प्राप्त नही हुई है, जिससे यह साफ दर्शित होता है कि उक्त लोगों के द्वारा मेरे साथ धोखाधडी/जालसाजी की गई है। जब हमारे क्षेत्र में यह परम्परा है कि राशि लेते समय सामने वाले के नाम पर रजिस्ट्री करना होती है और जब राशि वापस लौटा दी जाती है तब भूमि स्वामी के नाम वापस उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवा दी जाती है ऐसे हमारे क्षेत्र में सैकडों उदाहरण है जिसके तहत दोनों ही पक्षों में लेनदेन हुआ है और इसी परम्परा के चलते मुझे राशि की आवश्यकता होने पर मैने भी इन लोगों से राशि ब्याज पर उधार प्राप्त की थी, लेकिन मेरी जमीन की कीमत आज दिनांक करोडों रूपयें होने की वजह से यह लोग मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। उक्त मामले की जानकारी हमारे पूरे ग्रामवासियों को भी है वह भी इन लोगों के डर के कारण सामने नही आ रहे है क्योंकि यह लोग प्रभावशाली है।

शोभायात्रा में राम जी की 14 फिट की प्रतिमा हैदराबाद के कलाकारों द्वारा निर्मित मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी

श्री राम नवमी शोभायात्रा को लेकर बैठक संपन्न

धार। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभायात्रा को लेकर सर्व हिन्दू समाज द्वारा एक वृहद बैठक का आयोजन रखा गया जिसमे सभी राम भक्तो ने सर्व सम्मति से शोभायात्रा की रूप रेखा तय की। बैठक में अयोध्या जी से पधारे हनुमानगढ़ी महंत श्री सौरभ दास जी महाराज मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं संकटमोचन हनुमान जी महाराज की विधि-विधान से पूजन अर्चना कर की गई ।

उपस्थित सभी राम भक्तो ने शोभायात्रा को सफल बनाने हेतु अपने-अपने विचार रखें। निर्णय लिया गया कि इस वर्ष रामनवमी पर्व पर शोभायात्रा की शुरुआत प्रतिवर्ष अनुसार नगर के आन्देश्वर मंदिर एम जी रोड (राजवाड़ा) से हरिनाम संकीर्तन रामायण मंडल द्वारा भगवान राम जी की आरती कर प्रारंभ होगी। जो शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई निकलेगी ,जिसमे मुख्य रूप से हर्बोला बंधु अंकित पाटीदार एवं अंकित शर्मा अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे । शोभायात्रा में राम जी की 14 फिट की प्रतिमा हैदराबाद के कलाकारों द्वारा निर्मित मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी , साथ ही 11 फीट की विशालकाय हनुमान जी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। शोभायात्रा मे अपनी परम्पराओ का निर्वहन करते श्री हरिनाम संकीर्तन रामनारायण मंडल भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। सभी रामभक्तो ने अधिक से अधिक संख्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्स्व में शामिल होने के लिए सभी सनातनी हिन्दुओं से आग्रह किया है ।

विश्व में शहडोल के 'मिनी ब्राज़ील' विचारपुर की हो रही चर्चा : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

- फुटबॉल खिलाड़ियों को वितरित की खेल सामग्री

भोपाल । उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि फुटबॉल मानसिक, शारीरिक संतुलन बनाने का खेल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहडोल के 'मिनी ब्राज़ील' के नाम से पहचान बना चुके विचारपुर का जिक्र कई मंचों पर किया है जहां पर खिलाड़ी चार चार पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने शहडोल केमिनी ब्राज़ील' विचारपुर मैदान

पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सपना गुप्ता, सानिया कुंडे सुहानी कोल सहित अन्य फुटबॉल खिलाड़ियों को किट, फुटबॉल सहित अन्य खेल सामग्री का वितरण किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि 'मिनी ब्राज़ील' विचारपुर के लगभग हर घर में राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रदेश, संभाग, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं यह विंध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि विचारपुर के बच्चे बचपन से ही फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेचुरल प्रतिभा निखरना आसान होता है, इसके लिए प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने फुटबॉल खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कोच श्री रईस अहमद व अन्य फुटबॉल कोचों के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की।

1230 मेगावॉट विद्युत पारेषण के लिये मध्यप्रदेश में बनेंगे दो 400 के.व्ही. के सबस्टेशन

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश को आगामी दो से तीन वर्षों में दो चरणों में 1230 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त उपलब्धता रहेगी, इस हेतु बिजली कंपनी के मुख्यालय जबलपुर में आर.ई.सी. ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को ट्रांसमिशन एस.पी.व्ही. सौंपा। इस परियोजना के तहत मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड के बंधौरा (सिंगरौली) पावर जनरेटिंग प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी के लिये ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जाना है।

पारेषण अद्योसंरचना होगी विस्तारित

एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 1230 मेगावॉट विद्युत प्रदाय हेतु मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड से पॉवर परचेस अनुबंध किया था, उक्त हेतु मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड द्वारा 2X800 मेगावॉट क्षमता के पावर जनरेटिंग प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त पावर प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी के लिये नियामक आयोग के विनियमानुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के अंतर्गत पारेषण अद्योसंरचना के विस्तार हेतु मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी/एस.टी.यू. से अनुरोध किया गया था। इसके तहत शासन ने निविदा प्रक्रिया समन्वयक (बी.पी.सी.) के लिये आर.ई.सी.पी.डी.सी.एल. (आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड) को नियुक्त किया। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली (टी.बी.सी.बी) में मेसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 2000 करोड़ रूपये की इस परियोजना को अन्य बिडर्स के मध्य न्यूनतम दर के आधार पर हासिल करने में सफलता प्राप्त की।

पारेषण सेवा अनुबंध हस्ताक्षरित

श्री चक्रवर्ती ने जानकारी दी कि तमाम वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं मेसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मध्य पारेषण सेवा अनुबंध (ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित हुये। इसके तहत टी.बी.सी.बी. में 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. एवं 132 के.व्ही. की विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों सहित दो 400 के.व्ही. के सबस्टेशन रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन में स्थापित किये जाने हैं।

चैत्र नवरात्रि में पवित्रता एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर्व हिन्दू समाज ने दिया ज्ञापन

देवास। पवित्र हिन्दू पर्व चैत्र नवरात्रि में पवित्रता एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर्व हिन्दू समाज के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ज्ञापन की कॉपी पुलिस अधीक्षक एवं निगम आयुक्त को भी प्रेषित की गई। ज्ञापन में बताया कि पवित्र त्यौहार चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्रि पर्व देवास नगर की प्रमुख पहचान, पवित्रता व आस्था का पर्व है। जिसमें माता टेकरी पर देवास जिले व अन्य जिलों से लोग दर्शन हेतु बड़ी संख्या में आते है। किन्तु कुछ विधर्मियों द्वारा अवैध वसूली, अपवित्रता व अशांति फैलाई जाकर अव्यवस्था फैलाई जाती है। जिससे आर्थिक, सामाजिक व मानसिक क्षति पहुंचती है एवं भावनाएं आहत होती है। आस्था व पवित्रता का केंद्र माता टेकरी के अव्यवस्थित व असुरक्षित होने की संभावना बढ़ जाती हैं। सर्व हिन्दू समाज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि माताजी की टेकरी पर किसी भी विधर्मी या धर्म विरोधी को किसी भी प्रकार का टेंडर (लाइट, पानी, प्रसाद की दुकान, गाड़ी स्टैंड आदि) न दिया जाए। यदि पूर्व में कोई ऐसा टेंडर दे दिया गया है तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री सिंह के नेतृत्व में अध्ययन दल ने किया अयोध्या में सरयू नदी पर घाटों का भ्रमण

अयोध्या के सरयू घाटों की तर्ज पर जबलपुर में नर्मदा घाटों का होगा उन्नयन एवं पुनर्निर्माण

भोपाल (नप्र)। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज अयोध्या में सरयू नदी पर बने घाटों का भ्रमण किया। इस दौरान सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव, विभागीय सलाहकार समिति के सदस्य श्री प्रशांत पोल, विशेष सहायक श्री राहुल सिंह राजपूत, मुख्य अभियंता श्री गोपाल सिंह, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एवं डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मंत्री श्री सिंह के नेतृत्व में अध्ययन दल ने सरयू नदी पर नवनिर्मित घाटों की स्थापत्य कला, रामपथ, राम की पैड़ी, पार्किंग व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, म्यूरल वर्क और पर्यटकों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में यूपीपीसीएल से मुख्य अभियंता श्री राजेश कुमार, सरयू नहर डिवीजन के कार्यपालन यांत्रिक श्री पारस नाथ एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसपी भारती ने मंत्री श्री राकेश सिंह को सरयू नदी के तट पर नवनिर्मित घाटों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भ्रमण के दौरान इन अधिकारियों ने सरयू तट पर पर्यटकों के लिए विकसित सुविधाओं, श्रद्धालुओं के लिए निर्मित व्यवस्थाओं, भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को सचित्र रूप से दिखाने के लिए निर्मित म्यूरल वाल्स पर विस्तार से जानकारी दी।

मंत्री श्री सिंह ने भ्रमण के दौरान सड़क विकास निगम के अधिकारियों एवं डीपीआर बनाने वाली एजेंसी से कहा कि जबलपुर में नर्मदा नदी किनारे बनने वाले घाट धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक सुविधाओं के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि घाटों के निर्माण में माँ नर्मदा की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और पर्यावरणीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में नर्मदा नदी किनारे सरयू की तर्ज पर घाटों के निर्माण की घोषणा की थी। मंत्री श्री राकेश सिंह ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर तैयार करने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को दायित्व सौंपा है। अब तक तैयार योजना एवं विभिन्न स्तर पर हुए विचार विमर्शों के आधार पर मंत्री श्री सिंह ने बताया कि नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर के प्रमुख घाटों के सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत घाटों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रस्तावित योजना के तहत तिलवारा घाट और कालीधाम घाट पर नाव टर्मिनल स्थापित करने की योजना है, जिससे जलपर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साईं तीर्थम, खारीघाट, ग्वारीघाट और जिल्हेरीघाट पर फ्लोटिंग डेक बनाए जाएंगे। सभी प्रमुख घाटों के पास संगठित पार्किंग क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी।

विक्रम संवत्

डॉ.मुरलीधर चाँदनीवाला

कब तक अस्पृश्य रहेगा?

राष्ट्रीय कैलेंडर के लिये विक्रम संवत्

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन विक्रम संवत् के आरम्भ होने का दिन है। यह दिन विश्व के सबसे पहले गणतंत्र का स्थापना-दिवस होने के साथ-साथ सृष्टि के आरम्भ का भी दिन है। अब से 2082 वर्ष पहले शकों को परास्त कर मालव गणराज्य की जो अविस्मरणीय जीत हुई, उसे राष्ट्रीय गौरव का विषय माना जाता है। पूरा भारत आज भी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाता है। घर-घर, द्वार-द्वार गुड़ी बाँधने की परम्परा के कारण यह दिन गुड़ी पड़वा भी कहलाता है। गुड़ी विजयोल्लास की देवी है, नये संवत्सर की शुभ-संदेशवाहिका है। यह नव-संवत्सर की सनातन उषा ही है जो हमारे द्वार पर उत्सव बन कर आ खड़ी होती है।

जिस तरह हिन्दी का राष्ट्रव्यापी वर्चस्व होते हुए भी वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, उसी तरह विक्रम संवत् का चारों तरफ बोलबाला होते हुए भी वह राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं बन सका। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष 1957 में घोषित हुआ। दुर्भाग्यवश विक्रम संवत् को नहीं, शक संवत् को राष्ट्रीय कैलेंडर के लिये चुना गया। तब से लेकर अब तक विक्रम संवत् राष्ट्रीय कैलेंडर के लिये अस्पृश्य ही बना हुआ है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है? कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार ने धर्म-निरपेक्ष सिद्धांतों के दबाव में आकर विक्रम संवत् को पीछे धकेला, और शक संवत् को आगे किया। इस काम को ताकत मिली इस बात से कि शक संवत् ईस्वी सन् की तरह सौर गणना पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर बनाते समय केवल इस बात पर जोर था कि वही संवत् स्वीकार्य हो, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कदमताल कर सके। क्या यह दुःख का विषय नहीं, कि सब लोग जिस तिथिपत्र के अनुसार सारे तीज-त्यौहार मनाते हैं, महाकुम्भ जैसा विराट पर्व मनाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, लोक-कला और लोक-संस्कृति से जुड़ते हैं, वह महान् विक्रम संवत् स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा नहीं है। सब जानते हैं कि विक्रम संवत् सूर्य की गति पर नहीं,चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एक-एक दिन के कलात्मक सौन्दर्य के जादू से हम सब वाकिफ हैं। शक संवत् भले ही राष्ट्रीय पंचांग हो, लेकिन हम पर उसका कोई खास असर नहीं। वह विक्रम संवत् से केवल इक्कीस वर्ष पुराना है। उसे तो उसी दिन हाशिए पर डाल दिया जाना चाहिए था, जिस दिन हमारी संस्कृति पर आक्रमण करने वाले शक पराजित हुए, और विक्रम संवत् की पक्की नींव रखी गई। आश्चर्य है कि शक संवत् बनाये रखा गया। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर एक ओर से ईस्वी सन् को पकड़े हुए है, दूसरी ओर शक संवत् को। शक और हूणों ने आक्रमण कर हमारे देश को जो हानि पहुँचाई, उसका हिसाब होने से पहले ही हमें दूसरे विदेशी आक्रान्ताओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने हम पर राज किया, वे चले भी गये, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को ही सब कुछ मान लेने की मानसिकता ने हमसे अमूल्य संस्कार छीन लिये। उसने हमारा संवत् ही नहीं छीना, वह सब छीन लिया, जिस पर हम गर्व कर सकते थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिये जान-बूझकर शक संवत् को पकड़कर रखा। भारत स्वतंत्र हुआ, तब सत्ताधारियों ने भी उसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठाया। हमारे स्कूलों में इतिहास पढ़ाते समय आज भी ईसापूर्व (बी.सी.) और ईसापश्चात् (ए.डी.) का उल्लेख किया जाता है, जबकि विक्रमादित्य ही ईसा से 57 वर्ष पहले हुए। हमें कालगणना के अपने मानकों का प्रयोग करते रहने में क्या कठिनाई थी, यह समझ से परे है। विक्रम संवत् के आरम्भ को ईसा पूर्व 57 कहने की अपेक्षा विक्रम संवत् 01 कहने में भला क्या अड़चन हो सकती है? हमारे होनहार बच्चे पूरे विश्व की सूचनाओं से परिचित हैं, किन्तु भारतीय संस्कृति की बुनावट करने वाले विक्रम संवत् से उन्हें अनभिज्ञ रखने का पाप किसके माथे? हिन्दू संस्कृति की दुहाई देने वालों के परिजनों से और बच्चों से पूछ कर तो देखिए, कि अभी कौन सा संवत् चल रहा है? भगवान् करे, आप निराश हो कर जमीन में न धँस जाएँ।

सम्राट् विक्रमादित्य से ले कर राजा भोज के काल तक की लगभग दस सदियों में सनातन धर्म की शिक्षाओं के चलते हम जिस ऊँचाई पर थे, वह भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है। जब-जब शिक्षा में गिरावट आई, समाज का भी पतन हुआ। हमारे शिक्षक नई पीढ़ी को मिट्टी की गंध से दूर रखेंगे, तो वह संस्कारों से वंचित रहेगी और अपनी विरासत से भी। मैकाले की शिक्षा पद्धति को दोष देकर अपना बचाव करने वाली सरकारें तो आती-जाती रहेंगी, लेकिन हमें वे रास्ते खुले रखने होंगे, जो प्राचीन आचार्यों ने बनाए। आक्रान्ताओं के अधीन रहने का दुर्भाग्य झेलते हुए हम यहाँ तक आ गये, किन्तु जो आलोक-स्तम्भ हमारे पूर्वज हिन्दू नरेशों ने स्थापित किये थे, वे आज भी हमें आलोकित करते रहते हैं। विजय को समय की रेत के साथ फिसलने से बचाये रखने का ऐसा कोई और उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलता। आश्चर्य यह कि विक्रम संवत् ने हमें हिन्दू पंचांग ही नहीं दिया, अपितु वर्ष भर चलते रहने वाले तीज-त्यौहारों की सौगात भी दी। यह सौगात नहीं होती, तो हमारी लोक-चेतना न जाने कब टूट कर बिखर जाती। विक्रम संवत् अपने शुरुआती दौर में कृत संवत् था, कालान्तर में उज्जयिनी के मालव नरेशों की लोकप्रियता के चलते वह मालव संवत् के नाम से जाना गया। राजा भोज के समय के आसपास ही विक्रमादित्य के विरुद को अनंतकाल तक जीवन्त बनाये रखने के लिये लोक में विक्रम संवत् प्रचलित हुआ।

महान् हिन्दू सम्राट् विक्रमादित्य ने अपनी सभा के विद्वानों की सहायता ले कर जिस संवत् को मालव-संवत् या कृत संवत् नाम दे कर कालगणना का वटवृक्ष तैयार किया, उसे उनकी लम्बी वंश परम्परा ने सींचा। उसकी छाया में हल जोतते हुए किसान, श्रमिक, व्यापारी, श्रेष्ठी समाज, विप्र समुदाय, योद्धा, चिकित्सक और विद्या के क्षेत्र में अपनी फसल उगाने वाले महारथियों ने नये-नये कीर्तिमान रचे। उन्हीं की बदौलत हमें भारतीय इतिहास का वह स्वर्णयुग मिला, जिस पर आज भी हमें नाज है। हमारे आचार-विचार विक्रम संवत् के अनुशासन से बँधे हुए रहे हैं। विक्रम संवत् की जीवन-शक्ति और इसकी चमक सबसे निराली है। इस संवत् के मास, पक्ष और तिथियों का आधा-अधूरा ज्ञान होने के बावजूद नयी और पुरानी पीढ़ी के लोग विक्रम संवत् के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक रीति-रिवाज, जन्म-विवाह-मृत्यु से सम्बंधित सामाजिक व्यवहार, दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन सहित सारे पर्व और त्यौहार जिस तिथिपत्र के अनुसार मनाये जाते हैं, वह विक्रम संवत् पर ही निर्भर है।

विद्वानों के मतानुसार विक्रम संवत् ही आधुनिक है। इससे पहले के सप्तर्षि संवत, युधिष्ठिर संवत, वीर निर्वाण संवत्, बुद्धनिर्वाण संवत् प्रचलित हैं, किन्तु विक्रम संवत् की जीवन-शक्ति और इसकी चमक के आगे ये सब फीके होते चले गये। विक्रम संवत् ने हमारे सामाजिक जीवन को उत्सव बनाये रखने के लिये त्यौहारों का सृजन किया, सांस्कृतिक इतिहास की रचना की। इस संवत् ने संवत्सर और कालचक्र के विज्ञान को जीवन के उल्लास से जोड़ कर उस उत्सव-धर्म की नींव रखी, जो हमारे संघर्ष भरे दिनों में भी जीवन का उत्साह बनाये रखने के लिये वरदान सिद्ध हुई है। हम भारत के लोग दुःख के पहाड़ के नीचे दबे हों, तब भी हँस लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं। इस बात के सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास। अभाव और असुविधाओं में रह कर जीवन-यापन करने वाले ही हमारे यहाँ खुशमिजाज देखे गये हैं। ये ही वे लोग हैं जो हाट-मेले में दिखाई देते हैं, पंचकोशी की यात्रा में दिखाई देते हैं, तीर्थ में डुबकियाँ लगाते हुए दिखाई देते हैं, भजन-कीर्तन में झूमते हुए दिखाई देते हैं ,और अपनी थोड़ी सी जमा पूँजी दूसरों की भलाई के लिये दोनों हाथों से लुटाते हुए दिखाई देते हैं। ये वे लोग हैं, जो ज्यादा आधुनिक नहीं हुए, किन्तु उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो विक्रम संवत् ने हमें दी।

पुष्प-गुच्छ

मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल पटेल को पुष्प-गुच्छ भेंटकर अभिवादन किया।

74,697 किसानों से 5 लाख 80 हजार मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूँ खरीदी: खाद्य मंत्री राजपूत

757 करोड़ 36 लाख रूपये का हुआ भुगतान

भोपाल(नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 74697 किसानों से 5 लाख 80 हजार 711 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक 757 करोड़ 36 लाख रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। जिला उज्जैन में एक लाख 19 हजार 535, सीहोर में 83735, देवास में 60456, शाजापुर में 60282, इंदौर में 42765, भोपाल में 38640, राजगढ़ में 36457, मंदसौर 25292, आगर मालवा में 23604, धार में 20564, विदिशा में 19593, हरदा में 13451, खण्डवा में 11082, रतलाम में 10857, नीमच में 3351, नर्मदापुरम में 3307, झाबुआ में 2965, रायसेन में 2708, बैतूल में 1000, दमोह में 460, खरगौन में 329, गुना में 252, सागर में 22 और अलीराजपुर में 4 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है।

विश्व संवाद केंद्र में पुस्तक 'बरोह' का विमोचन और परिचर्चा का आयोजन

परिवार के बीच बढ़ती दूरियों को समाप्त करने में बरोह की होगी मुख्य भूमिका : डॉ. मनमोहन वैद्य

भोपाल। संघ ने शताब्दी वर्ष में कुछ पुस्तकों को आमजन तक पहुंचने का निर्णय लिया है। यह पुस्तक इसी श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है। मुझे याद आता है कि प्रा.प्र.ग. सहस्त्रबुद्धे द्वारा लिखित तरुण भारत में प्रकाशित होने वाले लेख पढ़ने के लिए मैं प्रत्येक शनिवार को उत्सुक रहता था। क्योंकि इन लेख में बहुत सरल भाषा में जीवन के संदेश, चुनौती और प्रसंग पढ़ने को मिलते थे। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. मनमोहन वैद्य ने गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र में आयोजित पुस्तक विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम में कही। डॉ. वैद्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने संस्कृति अध्येता, अकादमिक प्रशासक गिरीश जोशी द्वारा अनुवादित पुस्तक 'बरोह' का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने की।

उल्लेखनीय है कि गिरीश जोशी ने पुणे के प्रसिद्ध चिंतक, विचारक एवं लेखक प्रा.प्र.ग. सहस्त्रबुद्धे द्वारा जीवन की चुनौतियों का सहज समाधान देने के लिए सरल एवं रुचिकर प्रसंगों पर आधारित मराठी पुस्तक 'पारंब्या' का हिन्दी अनुवाद किया है। कार्यक्रम का आयोजन पुस्तक प्रकाशित करने वाली संस्था श्रीभारती प्रकाशन, नागपुर द्वारा किया गया।

परिवार में बढ़ रही दूरियां

इस अवसर पर डॉ. मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ ने शताब्दी वर्ष में जिन पांच विषयों पर कार्य करने का निश्चय किया है उसमें कुटुंब प्रबोधन प्रमुख है। आज के समय में करियर की चाह में परिवार के साथ बैठना नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया ने दुनिया के लोगों से तो हमें जोड़ दिया है लेकिन परिवार के सदस्यों से दूरियां बढ़ा दी है। इसलिए आवश्यक है कि हम मोबाइल फोन बंद साइलेंट रखे, टेलीविजन बंद करे और परिवार के साथ अपनों के साथ बैठे। पुस्तक पर चर्चा करते हुए डॉ. वैद्य ने कहा कि हम सभी परिवार के लोगों के साथ बैठे, उनसे पुस्तक पर चर्चा करे, इसमें शामिल छोटी छोटी कहानियों पर चर्चा करें तभी इस पुस्तक की सार्थकता बनेगी। इस दौरान उन्होंने पुस्तक की कहानी छुट्टी और विक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। इसी क्रम ने उन्होंने कहा कि हमें यह बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि वैल्यू अलग है और स्किल्स अलग। अगर हम यह बात अच्छे से समझ लें और दोनों शब्दों के अर्थ को बेहतर ढंग से जान लें तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंत में डॉ. वैद्य ने कहा कि हमें साथ बैठना है, अतीत को झांकना है और भविष्य के स्वप्न देखना है।

पुस्तक की हर कहानी है प्रासंगिक: इस अवसर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि मैंने कई किताबें पढ़ी जिनका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ और वह किताब कहीं न कहीं अपने प्रवाह छोड़ देती है। लेकिन इस किताब को गिरीश जोशी जी ने जिस सूझबूझ के साथ अनुवादित किया वह आपको अंत तक बांधे रखने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि हिंदी के पाठकों को जोड़ने के लिए यह जो पहल की गई है वह सराहनीय है। उन्होंने आगे भी इस तरह की श्रृंखला को जारी रखने की बात कही।

इस दौरान पुस्तक के बारे में गिरीश जोशी ने कहा कि 125 पृष्ट की इस पुस्तक में 48 लेख और प्रसंग शामिल है। उन्होंने कहा कि विद्वान वही है जो कठिन भाषा को सरल और सहज ढंग से आमजन तक पहुंचा सके, सहस्त्रबुद्धे जी ने वही कार्य किया है। 'बरोह' का संबंध वटवृक्ष से होता है। 'बरोह' का नाम सुनते ही आँखों के सामने वटवृक्ष आ जाता है। अन्य वृक्षों की भी अनेक शाखाएँ होती है, लेकिन 'बरोह' तो केवल वटवृक्ष का ही वैभव है। वटवृक्ष की शाखाओं से 'बरोह' नीचे उतरकर पुनः धरती में प्रविष्ट होती है और एक नवीन वटवृक्ष को जन्म देती है। ऐसा वृक्ष जो नया होने के बावजूद पुराने से जुड़ा रहता है। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन डॉ. अंशुल राय और आभार प्रदर्शन मंगेश जोशी ने किया।

किसानों को डीएपी की बोरी 1350 रूपये में मिलेगी : शिवराज

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2025 (01.04.2025 से 30.09.2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ सीजन 2025 के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड़ रुपये होगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।

राजगढ़ में ब्रेक फेल ट्रक ने बाइकों को मारी टक्कर

- नदी में गिरे सात लोग, दो की हालत गंभीर; महिला और बच्चा भोपाल रेफर

राजगढ़ (भोपाल) (नप्र)। राजगढ़ में शुक्रवार को ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। खोयरी मंदिर के पास ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद वह 200 मीटर तक भीड़भाड़ वाली बस्ती से गुजरता रहा। नेवज नदी के पुल पर ट्रक ने टक्कर मारी जिससे बाइक पर सवार सभी सात लोग 15 फीट नीचे नदी में जा गिरे। प्लाई से भरा ट्रक भी पुल पर पलट गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। बाकी पांच घायलों का इलाज राजगढ़ जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

ड्राइवर हॉर्न बजाते और चिल्ला रहा था: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक कालीपीठ की तरफ से आ रहा था। ड्राइवर हॉर्न बजाते और चिल्लाते हुए लोगों को रास्ते से हटने की चेतावनी दे रहा था। इससे बस्ती में बड़ा हादसा टल गया। हादसे में घायल हुए लोगों में हमीरपुरा गांव के जगदीश, लीला बाई और सुरेश हैं। दूसरी बाइक पर बख्तारपुरा के देवी सिंह, सुगन बाई, राजेश और 9 वर्षीय चंपालाल सवार थे। सुगन बाई और चंपालाल की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भोपाल रेफर किया गया है।

इंदौर शहर में 5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य पूर्ण

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी केंद्र एवं राज्य शासन की प्राथमिकता वाली स्मार्ट मीटर परियोजना का अत्यंत तेजी से प्रभावी रूप से संचालन कर रही हैं। शुक्रवार को इंदौर शहर में स्मार्ट मीटर स्थापना का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पश्चिम क्षेत्र कंपनी के कार्मिकों को बधाई दी है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर सेल के साथ ही जिलों की टीम स्मार्ट मीटर परियोजना का बहुत ही गंभीरता से संचालन कर गुणवत्ता से मीटर स्थापना, सटीक रीडिंग, डाटा कलेक्शन, त्रुटिरहित बिलिंग इत्यादि कार्य कर रही हैं। एमडी श्री सिंह ने बताया कि उपभोक्ता सेवाओं में वृद्धि करते हुए स्मार्ट मीटरीकरण तेजी से जारी हैं। इसी के तहत इंदौर शहर में 5 लाख 500 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। यह संख्या मप्र के किसी भी शहर में सर्वाधिक हैं। इंदौर के बाद कंपनी क्षेत्र के उज्जैन जिले में 1.12 लाख, रतलाम जिले में 1.10 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अन्य जिलों में 10 हजार से 55 हजार स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं। कंपनी क्षेत्र में 11.46 लाख स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में करीब ढाई से 3000 स्मार्ट मीटर प्रतिदिन लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर रूफ टॉप सोलर नेट मीटर एवं टाइम ऑफ द डे बिल प्रणाली में भी कारगार साबित होकर उपभोक्ताओं को रियायत दिला रहे हैं।

मैं तुम्हारी रुक्मिणी... छात्रा ने बोर्ड एग्जाम में भगवान कृष्ण के लिए लिखा एप्लिकेशन

कहा- मुझे फेल किया तो बुरी दुआ दूंगी

अशोकनगर (नप्र)। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि मूल्यांकन के दौरान बच्चों की कॉपी में अजब-गजब उत्तर लिखे गये हैं। कई परीक्षार्थियों ने पास होने के लिए उत्तर पुस्तिका में आग्रह भी किया है। इसे पढ़कर मूल्यांकन कर रहे शिक्षक भी हैरान हैं। बता दें कि प्रशासन की निगरानी में तीन चरणों में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन चल रहा है। मूल्यांकन के दौरान कक्षा 10वीं के एक छात्र ने अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में पास होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही एप्लीकेशन लिख दिया है। उसने पास करने का आग्रह करते हुए पुस्तिका के नीचे अपने आप को रुकमणी बताया है।

सर तेरी कसम मुझे पास कर देना

नाम बताने की शर्त पर कॉपी चेक करने वाले एक टीचर ने बताया कि 10वीं के एक और छात्र ने अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में लिखा है कि सर तेरी कसम पास कर देना, मुझे फेल किया तो बुरी दुआ दूंगा। वहीं एक दूसरे छात्र ने टीचर को चेतावनी देते हुए लिखा है कि दम है तो मुझे पास करके दिखाओ। एक दूसरे छात्र ने तो उसे पास करने के लिए आग्रह करते हुए लिखा है कि आप सर हो या मैडम हो, आप सख्त हो या सॉफ्ट हो मुझे पास कर देना, नहीं तो घर वाले शादी कर देंगे।

डॉ. जवाहर कर्नावट का मुंबई विवि में व्याख्यान आज

भोपाल। प्रदेश के प्रखर वक्ता-लेखक एवं भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मान से अलंकृत डॉ. जवाहर कर्नावट को मुंबई विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान हेतु विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। 'हिंदी भाषा एवं साहित्य में कौशल विकास' विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉ. कर्नावट 29 मार्च को आयोजित सत्र 'हिंदी नाटक, सिनेमा, विविध कलाएं और कौशल विकास' सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। इस सत्र के प्रमुख अतिथि प्रख्यात अभिनेता एवं साहित्यकार श्री अखिलेश मिश्रा होंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से प्राध्यापक तथा शोधविद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं।

भाजपा-कांग्रेस पार्षदों के बीच दे दना दन

रीवा नगर निगम में बजट बैठक के दौरान हंगामा

रीवा (नप्र)। मध्य प्रदेश के रीवा में नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। नेताओं ने एक-दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। यह सब महापुरुषों की मूर्तियों के सम्मान को लेकर शुरू हुआ। बजट में मूर्तियों के नामों के आगे सम्मानित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे विवाद बढ़ गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है और नेता एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ देर के लिए नगर निगम अखाड़ा बन गया। दरअसल, बैठक में शहर में महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। बजट में इन मूर्तियों के नाम लिखे गए थे। बहस तब शुरू हुई जब पार्षद समीर शुक्ला ने कहा कि बजट में परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यमुना प्रसाद शास्त्री और 15 अन्य हस्तियों के नामों के आगे सम्मानित शब्द नहीं लिखा गया है।

रोकनी पड़ी कार्रवाई: समीर शुक्ला ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने गुस्से में कहा कि हम इस बजट की अर्थी निकालते हैं। उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि यह लिपिकीय त्रुटि है, यानि लिखने में गलती हुई है। लेकिन बीजेपी के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष माफी की मांग पर अड़े रहे। वे नगर निगम अध्यक्ष के सामने जाकर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख नगर निगम अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी।

बीच बचाव करने महापौर को आना पड़ा: कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। तभी कांग्रेस पार्षद मनीष नामदेव पानी की बोतल लेकर आए और गंगाजल बोलते हुए सभी पार्षदों और अध्यक्ष के ऊपर छिड़कने लगे। इससे सदन में फिर से हंगामा मच गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षद आपस में धक्का-मुक्की करने लगे। स्थिति को संभालने के लिए रीवा के महापौर और निगम अध्यक्ष को बीच-बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। इस घटना के बाद सभी नेता अपनी-अपनी सफाई दे रहे हैं। वे एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे पक्ष ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था।

जांच के आदेश

समीर शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस ने महापुरुषों का अपमान किया है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है। महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

॥ मंदिरम् ॥

69

हलासुरू सोमेश्वर मंदिर, कर्नाटक

हलासुरू सोमेश्वर मंदिर भारत के बेंगलुरु, कर्नाटक में हलासुरू के पड़ोस में स्थित है। यह चोल काल के शहर के पुराने मंदिरों में से एक है, यह हिंदू भगवान शिव को समर्पित है । प्रमुख परिवर्धन या संशोधन हिरिया केम्पे गौड़ा द्वितीय के शासन के तहत विजयनगर साम्राज्य काल के दौरान किए गए थे। सोमेश्वर मंदिरों का निर्माण कर्नाटक में कल्याणी के चालुक्यों द्वारा किया गया था। उस अवधि के दौरान हम तमिल शिलालेखों को देखते हैं क्योंकि कुछ मुदलियार (तुलुवा वेल्लाला) को बसाया गया था। ये मुदलियार , मूल रूप से तुलु भाषी, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों विशेषकर अरकोट में बस गए थे। मंदिर का प्रबंधन मुज़राई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को सौंपा ट्रांसमिशन एसपीव्ही

1230 मेगावॉट विद्युत पारेषण के लिये मध्यप्रदेश में बनेंगे दो 400 के.व्ही. के सब-स्टेशन

भोपाल(नप्र)। मध्यप्रदेश को आगामी दो से तीन वर्षों में दो चरणों में 1230 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त उपलब्धता रहेगी। इसके लिये बिजली कंपनी के मुख्यालय जबलपुर में आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को ट्रांसमिशन एसपीव्ही सौंपा। इस परियोजना के तहत मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड के बंधौरा (सिंगरौली) पॉवर जनरेटिंग प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी के लिये ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जाना है।

पारेषण अद्योसंरचना होगी विस्तारित- एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने 1230 मेगावॉट विद्युत प्रदाय हेतु मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड से पॉवर परचेस अनुबंध किया था। मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड द्वारा 2X800 मेगावॉट क्षमता के पॉवर जनरेटिंग प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। पॉवर प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी हेतु नियामक आयोग के विनियमानुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के अंतर्गत पारेषण अधोसंरचना के विस्तार हेतु मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी/ एस.टी.यू. से अनुरोध किया गया था। शासन ने निविदा प्रक्रिया समन्वयक (बी.पी.सी.) के लिये आर.ई.सी.पी. डी. सी.एल. (आरईसी पॉवर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड) को नियुक्त किया। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली (टीबीसीबी) में मेसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 2000 करोड़ रूपये की इस परियोजना को अन्य बिडर्स के मध्य न्यूनतम दर के आधार पर हासिल करने में सफलता प्राप्त की।

पारेषण सेवा अनुबंध हस्ताक्षरित- श्री चक्रवर्ती ने जानकारी दी कि वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी एवं मेसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मध्य पारेषण सेवा अनुबंध (ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित हुये, जिसके तहत टी.बी.सी.बी. में 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. एवं 132 के.व्ही. की विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों सहित दो 400 के.व्ही. के सब-स्टेशन रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन (मैहर) में स्थापित किये जाने है।

मप्र में 5वीं और 8वीं बोर्ड के परिणाम घोषित

कक्षा 5वीं में 92.70 प्रतिशत और 8वीं में 90.02 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के परिणाम शुक्रवार दोपहर 1 बजे

जारी कर दिए गए। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक हरजिंदर सिंह ने परीक्षा पोर्टल पर रिजल्ट बटन दबाकर परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम 92.70 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के 90.97व से बेहतर है। इसी तरह, कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 90.02 प्रतिशथ रहा, जो पिछले वर्ष के 87.71 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

बालिकाओं का प्रदर्शन बेहतर

कक्षा 5वीं में बालिकाओं के पास होने का प्रतिशत 94.12 प्रतिशत और बालकों का 91.38 प्रतिशत रहा। वहीं, कक्षा 8वीं में बालिकाओं का पास होने का प्रतिशत 91.72 प्रतिशत और बालकों का 88.41 प्रतिशत रहा।

रिजल्ट के हिसाब से टॉप 10 जिले

कक्षा 5वीं के परिणामों में शीर्ष 10 जिले शहडोल, चंबल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर और भोपाल।

कक्षा 8वीं के परिणामों में शीर्ष 10 जिले- नरसिंहपुर, अलीराजपुर, रीवा, झाबुआ, बालाघाट, अनूपपुर, सीहोर, डिंडोरी, बड़वानी और मंदला।

भोपाल में 14 प्रतिशत बढ़ेगी प्रापर्टी दरें

कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्ताव पर बोले सांसद यह असंतुलित,जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ही नहीं की

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सांसद आलोक शर्मा ने आपत्ति ली है। उन्होंने कहा, प्रस्ताव का विरोध नहीं है, पर भोपाल में गाइडलाइन असंतुलित है। कहीं 100 प्रतिशत तो कहीं 500 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर, जनप्रतिनिधियों की बैठक भी नहीं की गई है। वहीं, साल 2006 से 2024 का डेटा तक अधिकारियों ने अब तक नहीं दिया है।

बता दें कि राजधानी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। कुल 1283 लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन एवरेज 14 प्रतिशत तक बढ़ाई जा रही है। विरोध और दावे-आपत्ति के बाद प्रस्तावित गाइडलाइन में 4 प्रतिशत का बदलाव किया गया है। गुरुवार शाम को भोपाल समेत 12 जिलों के पिछले 5 साल के आंकड़े दिखाकर गाइडलाइन फाइनल कर दी गई थी। इसके बाद यह केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी को भेज दी गई। निर्णय होते ही जनप्रतिनिधियों की नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर शुक्रवार शाम को होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की मीटिंग में सांसद शर्मा मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से बात की जाएगी। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि गाइडलाइन असंतुलित है। कहीं 100 प्रतिशत तो कहीं 500 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया, शहर में कलेक्टर गाइडलाइन की

दरों का असंतुलन हो चुका है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिछली बार कहा था कि भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन तय करने के पहले जन प्रतिनिधियों से बैठक की जाएगी, यह भी नहीं हुआ है। किस साल कितनी प्रतिशत गाइडलाइन बढ़ाई गई, ये डेटा भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसकी स्टडी से ही पता चल पाएगा कि बढ़ाने में फायदा है या घटाने में।

पिछली बार प्रस्तावित गाइडलाइन रोक दी गई थी- पिछले साल नवंबर में साल की दूसरी (संशोधित) गाइडलाइन प्रस्तावित की गई थी। इसमें 1283 लोकेशंस पर जमीनों के भावों में 5 से 200 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। उस समय भाजपा सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान सबनानी, रियल एस्टेट कारोबारियों की संस्था क्रेडाई भोपाल ने इसका विरोध किया था। वे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से भी मिले थे। इसके बाद इसे टाल दिया गया था। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक गुरुवार को हुई थी। जिसमें 14 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने प्रस्ताव है।

कुल 55 दावे-आपत्ति आए, इनमें से 37 खारिज कर दिए गए- गाइडलाइन के लिए दावा-आपत्ति मांगे गए थे, जो 55 आए थे। इनमें से 11 को पूर्णत- मान्य किया गया, जबकि 7 सुझावों को आंशिक रूप से मान्य किया गया।

बैठक में यह निर्णय लिया

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के माध्यम से यदि कोई संपत्ति एक साल के अंदर विक्रय की जाती है तो देय मुद्रांक शुल्क पर छूट का प्रावधान निर्धारित किए जाने संबंधी लेख किया जाए। दो या तीन वर्ष में विक्रय होने पर मुद्रांक शुल्क में अनुपातिक रूप से छूट प्रदान किए जाने के प्रावधान किए जाए। उक्त प्रावधान से भोपाल एवं मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में भी निवेश में वृद्धि होगी। जिला मूल्यांकन समिति में विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्रेडाई द्वारा दिए गए सुझाव के अनुक्रम में कृषि भूमि संबंधी उपबंधों में बदलाव किए जाने की अनुशंसा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित करने का निर्णय लिया। विधायक सबनानी के निर्देशों के अनुक्रम में पंजीयन अधिकारियों द्वारा भोपाल जिले में पिछले 5 वर्ष में गाइडलाइन की बढ़ोत्तरी के संबंध में अन्य राजभोगी जिलों से तुल्नात्मक स्थिति प्रस्तुत की गई।

'महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन उकसा सकती है'

- एमपी हाईकोर्ट की टिप्पणी, आरोपी की मां को बनाया था सह-आरोपी

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में उकसावे की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल और जस्टिस प्रशांत गुप्ता ने अपने निर्णय में कहा है कि भले ही कोई महिला स्वयं बलात्कार के लिए आरोपी नहीं हो सकती, लेकिन वह आईपीसी की धारा 109 के तहत बलात्कार के लिए उकसाने का अपराध जरूर कर सकती है। लिहाजा, रेप के लिए उकसाने वाली महिला के खिलाफ भी 376, 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बताने गई थी- शादी के लिए राजी हूं: भोपाल के छोला मंदिर थाने में 21 अगस्त 2022 को एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं सहमत हो गई थी। मैं कुछ समय बाद उसकी मां और भाई को अपनी सहमति बताने उनके घर गई थी। तब उस व्यक्ति की मां और भाई ने जबरन मुझे उसके कमरे में भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मुझसे शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार), 190 (लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

आरोपी की मां-भाई को बनाया था सह-आरोपी

सरकारी वकील सीएम तिवारी ने बताया कि आरोपी ने 22 अगस्त 2023 को भोपाल सेशन कोर्ट से जारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें भोपाल की निचली अदालत ने मुख्य आरोपी के साथ उसकी मां और भाई को भी सह आरोपी बनाया था। आरोपी अभिषेक गुप्ता पर शादी के नाम पर रेप करने का आरोप था। इस वारदात के समय आरोपी की मां और भाई भी मौके पर मौजूद थे। महिला ने रेप की घटना में शामिल होने का आरोप लगाया था।

मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के आंसू पोंछती है और उनका सहारा बनती है संबल योजना : मुख्यमंत्री

सभी का जीवन बेहतर हो और हर परिवार में सुख के सूरज का उदय हो

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा भी ऐसी जरूरतें होती हैं, जिनके लिए पैसा जरूरी होता है। प्रसूति, बीमारी, दिव्यांगता और किसी अपने को खो देने जैसे मुश्किल समय में कई बार हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। संबल योजना ऐसे ही मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के आंसू पोछती है और उनको सहारा प्रदान करती है।

राज्य सरकार प्रदेश के गरीब और श्रमिक वर्ग के कल्याण तथा उनका भाग्य बदलने के लिए दृढ़ संकल्पों के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प की भावना के अनुरूप अंत्योदय के कल्याण के संकल्प को प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खातों में 550 करोड़ रूपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद परिवारों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पांच हितग्राहियों से वर्चुअली बातचीत कर उनके परिजन के अवसान पर संवेदनाएं प्रकट की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों, नगर निगमों, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के हितग्राही और जनप्रतिनिधि भी वर्चुअली

जुड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पौधा भेंटकर स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के श्रमिक परिवारों का अभिवादन करते हुए कहा कि परिश्रम से अपने और अपने परिवार का जीवन चलाने वाले श्रमिक ही प्रदेश के विकास की नींव हैं। परिश्रम से ही हमारी प्रतिभा निखरती है और आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य का मार्ग भी बनता है। राज्य सरकार ने जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। पढ़ाई में अच्छा कर रहे विद्यार्थियों को स्कूटी और लेपटॉप देकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी प्रदेशवासियों का जीवन बेहतर हो। हर परिवार में सुख के सूरज का उदय हो और आनंद और वैभव के साथ सभी जीवन व्यतीत करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार शुचिता- पारदर्शिता और दक्षता के साथ जनकल्याण और विकास के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में संबल योजना का बैकलॉग भी समाप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि संबल योजना में अब तक 6 लाख 58 हजार से अधिक परिवारों को 5 हजार 927 करोड़ रूपए से अधिक के हितलाभ दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को असंगठित श्रमिक मानते हुए 01 मार्च 2024 से उन्हें संबल योजना में उन्हें शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयः योजना में शामिल किया गया है।

गरीब बहनों को गर्भावस्था के समय काम पर न जाना पड़े और उन्हें पोषण भी मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसी बहनों को 16 हजार रूपए देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से जुड़े संबल योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा की। इस क्रम में उन्होंने मंदसौर की श्रीमती अंजली रैकवार, खरगोन की श्रीमती प्रेमलता कर्मा, शहडोल की श्रीमती मन्नू ढीमर, दतिया की श्रीमती कल्लन वाल्मीक, सीहोर की श्रीमती शिव कुमारी से बातचीत की। श्रीमती अंजली रैकवार के पति के निधन पर 4 लाख रूपए तथा शेष चार हितग्राहियों को 2-2 रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से चर्चा में मंदसौर की श्रीमती अंजली रैकवार ने बताया कि इस सहायता से उन्हें पर्याप्त सहारा मिला और वे अब ब्यूटी पार्लर का कार्य सीख रही हैं।

बांधवगढ़ में एलीफेंट सफारी की संभावना

पर्यटकों के साथ रच-बस गए जंगली-हाथी

उमरिया (नप्र)। जंगल में जिस तरह से पर्यटक बाघ देखने के लिए उत्सुक होते हैं, उसी तरह से जंगली हाथियों को भी खुले जंगल में देखना पर्यटकों के लिए रोमांचकारी होता है। यह रोमांच पर्यटकों को देश के दक्षिण भारत में ही मिल पाता है, लेकिन अब इसकी संभावना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी नजर आने लगी है।

वर्ष 2018 में यहां आए जंगली हाथी, अब सहज होने लगे हैं। अब इन्हें जंगल में जिप्सियों को देखकर कोई भय नहीं होता और वे सामान्य ढंग से अपनी गतिविधियों में जुटे रहते हैं। जबकि पहले यह जंगली हाथी पर्यटकों के वाहन को देखकर उन्हें दौड़ाने की कोशिश करते थे।

सभी हिस्सों में दिखाई देने लगे हाथी- बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लगभग सभी हिस्सों में जंगली हाथी दिखाई देने लगे हैं। दरअसल, हाथियों के छोटे-छोटे झुंड बन गए हैं और यह झुंड जंगल के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं। कई जगह तो अकेला हाथी भी दिखाई देता है।

अब 80 के करीब पहुंच गई हाथियों की संख्या

यहां खास बात यह है कि कहीं भी जंगली हाथियों ने पर्यटकों को देखकर उन पर हमले का प्रयास नहीं किया। पार्क प्रबंधन के अनुसार बांधवगढ़ में जंगली हाथियों की संख्या करीब 80 है। बता दें कि वर्ष 2018 में जब जंगली हाथियों ने बांधवगढ़ में प्रवेश किया तो वे पर्यटकों के लिए खतरा बन गए थे। वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक खितौली में कई महीने तक पर्यटन रोकना पड़ गया था। इसी तरह से ताला में भी पर्यटन पर रोक लगा दी गई थी। इसकी वजह यह थी कि जंगली हाथियों ने अलग-अलग घटनाओं में पर्यटकों के वाहनों को काफी दूर तक दौड़ाया था। इस तरह की घटनाओं के चलते पार्क प्रबंधन ने सुरक्षा के लिहाज से पर्यटन रोक दिया था।

सुरक्षा पर पूरा ध्यान

जंगल में जंगली हाथियों की मौजूदगी की वजह से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए शुरू से ही जिप्सी चालक और गाइड को अलर्ट किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए बांधवगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने बताया कि जिप्सी चालकों और गाइड को लगातार इस बात की हिदायत दी जाती है कि वह जंगली हाथी दिखने पर उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखें, ताकि पर्यटक खतरे में ना आएं।

प्रोजेक्ट एलीफेंट है जरूरी

टाइगर रिजर्व में जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है और उनकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए काम होता है, उसी तरह से जंगली हाथियों के लिए भी प्रोजेक्ट एलीफेंट की मांग लंबे समय से मध्य प्रदेश में हो रही है।

बांधवगढ़ के खितौली, मगधी, ताला में हाथियों के छोटे झुंड और अकेला हाथी नजर आता है, जबकि पनपथा और पतौर में ज्यादा संख्या में जंगली हाथी नजर आते हैं।

पिछले एक सप्ताह के अंदर खितौली और ताला में पर्यटकों ने जंगली हाथी को देखा और रोमांचित हुए।